● वर्ष-3
● अंक-272
रायपुर, रविवार
23 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› 18 साल की उम्र में कास्टिंग काउच...

एनटीए मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठित, शिक्षा मंत्री बोले-

छात्र हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता-धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को एनईईटी और यूजीसी-नेट विवाद के बीच परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। यह कदम एनईईटी-यूजी और यूजीसी नेट समेत विभिन्न शीर्ष परीक्षाओं के पेपर लीक पर विवाद के बाद आया है, जिसे इसके आयोजन के एक दिन बाद रद्द कर दिया गया था, जो एक सप्ताह से अधिक समय से जारी है। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह सभी कदाचारों को समाप्त करने और एनटीए में सुधार की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने लिखा कि पारदर्शी, छेड़छाड़-मुक्त और शून्य-त्रुटि परीक्षा एक प्रतिबद्धता है। विशेषज्ञों की उच्च-स्तरीय समिति का गठन परीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करने, सभी संभावित कदाचारों को समाप्त करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और एनटीए में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की श्रृंखला में पहला है। उन्होंने कहा कि छात्र हित और उनका उज्ज्वल भविष्य सदैव हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। पैनल के अन्य सदस्यों में डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स दिल्ली, प्रोफेसर बी जे राव, कुलपति, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास, पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य- कर्मयोगी भारत, प्रो. आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी दिल्ली, गोविंद जयसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्र ने परीक्षा सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति को अधिसूचित करते हुए दो महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

नीट पीजी परीक्षा भी स्थगित

केंद्र सरकार ने हालिया परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मद्देनजर नीट-पीजी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कल होने वाली नीट पीजी परीक्षा को टाल दिया गया है और एग्जाम की नई तारीखों का एलान जल्द ही कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता पर आरोपों की हालिया घटनाओं को देखते हुए फैसला किया गया है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनिशेन द्वारा मेडिकल छात्रों के लिए कराई जाने वाली नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया की मजबूती का संपूर्ण विश्लेषण किया जाना जरूरी है। मंत्रालय ने आगे कहा, ''स्वास्थ्य मंत्रालय छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। यह निर्णय छात्रों के सर्वोत्तम हित में और परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है।'' गौरतलब है कि आज ही नीट-पीजी परीक्षा कराने वाले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनिशेन फॉर मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के अध्यक्ष और सदस्य, गवर्निंग बॉडी के ओएसडी डॉ. राकेश शर्मा ने कहा था कि हम देश की आशा को कम नहीं होने देंगे। हम पूरे देश में कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) मोड के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उन्होंने दावा किया था कि एनबीईएमएस के पास परीक्षा आयोजित करने के लिए मजबूत एसओपी हैं, जिसके कारण एनबीईएमएस साल-दर-साल सफलतापूर्वक परीक्षा दे रहा है। इन एसओपी का सख्ती से पालन किया जाता है। एनबीईएमएस ने बहुत मेहनत की है। प्रश्नपत्र की गोपनीयता बनाए रखने पर और प्रश्नपत्र के लीक होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, अब मंत्रालय ने इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है।

कांग्रेस ने बताया 'डैमेज कंट्रोल' की कोशिश

कांग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक कानून लागू करने के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले की शनिवार को आलोचना की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कानून - सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 - कई घोटालों के बाद लागू किया गया था और इसे क्षति नियंत्रण के लिए एक कदम बताया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को अपनी सहमति दी थी। रमेश ने कहा कि इन तीन दूरगामी विधेयकों को बिना उचित बहस और चर्चा के संसद से मनमाने ढंग से पारित कर दिया गया था।

एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार पद से हटाए गए

एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। इसी के साथ उन्हें अनिवार्य वेट करने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि हालिया परीक्षाओं में अनियमितताओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि सिंह को अगले आदेश तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में 'अनिवार्य प्रतीक्षा' में रखा गया है। बताया गया है कि भारतीय व्यापार प्रचार संगठन के चेयरमैन और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) को रद्द कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-स्नातक) में भी पेपर लीक के आरोप हैं और इसे रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि, सरकार इस मामले में अभी जांच कर रही है।

यूपी-हरियाणा बॉर्डर से सबसे पहले लीक हुआ था नीट का पेपर

नीट पेपर लीक मामले में नई जानकारी सामने आई हैय्। कहा जा रहा है कि नीट का पेपर बिहार नहीं बल्कि सबसे पहले यूपी और हरियाणा के बॉर्डर के पास स्थित किसी एग्जाम सेंटर से लीक किया गया था।

इसके बाद इसे बिहार समेत अन्य जगहों पर प्रसारित किया गया। नीट पेपर लीक कांड में उत्तर प्रदेश के मेरठ की जेल में बंद रवि अत्री की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आ रही है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सॉल्वर एवं सेटर अतुल वत्स्य और अंशुल सिंह के तार भी यूपी के माफिया गिरोह रवि अत्री से जुड़ रहे हैं। उसने जेल के अंदर से ही नीट पेपर लीक का पूरा तानाबना बुना। मेडिकल एंट्रेंस के लिए देश भर में 5 मई को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया था।

इससे एक दिन पहले 4 मई की रात को बिहार के पटना जिले के खेमनीचक इलाके में स्थित लर्नेड प्ले स्कूल में 35-40 अभ्यर्थियों को नीट का पेपर और उत्तर रटवाया जा रहा था। पुलिस ने जब यहां छापेमारी की तो 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही मौके से कई कागजातों के साथ प्रश्न-पत्र के जले हुए टुकड़े भी मिले। इसी से पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है। बिहार ईओयू ने जले हुए प्रश्न-पत्र के अवशेष पर दर्ज अधूरे कोड के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की कि यह लीक कहां से हुआ।

ईओयू की जांच अब बिहार से बाहर झारखंड और यूपी एवं हरियाणा तक पहुंच गई है। झारखंड के देवघर में ईओयू ने छापेमारी कर शुक्रवार रात को 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बालदेव कुमार उर्फ सिंटू उर्फ चिंटू, पंकु कुमार, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू शामिल हैं। इनमें से 5 बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। ईओयू इन्हें पटना लाकर किसी गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है।

नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन?

नीट पेपर लीक की जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसके मास्टरमाइंड भी बदल रहे हैं। पहले पटना से गिरफ्तार पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यदुवंशी को इसका सरगना माना जा रहा था। बाद में और खुलासे हुए तो नालंदा जिले के निवासी संजीव मुखिया को सरगना माना गया। वह अभी तक फरार चल रहा है। मगर अब यूपी की जेल में बंद रवि अत्री को पूरे पेपर लीक कांड का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। हालांकि, अभी तक ईओयू ने आधिकारिक रूप से उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं की है।

जीएसटी बैठक में लिए कई फैसले

रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर

दूध के डिब्बों-सोलर कुकर पर 12% कर

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने कर मांग नोटिस के दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई। उन्होंने कहा कि आज, जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए मांग नोटिसों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत विवरण शामिल नहीं हैं। उन सभी नोटिसों के लिए जो वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए थे, परिषद ने मांग नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 के लिए 30-11-2021 तक दायर किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा और 20-21 को 2011 से 2021 तक माना जा सकता है। इसलिए 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से उसी अपेक्षित संशोधन के लिए, परिषद ने एक सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न भरने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाने की सिफारिश की है, परिषद ने इसे 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश की है। यह वित्तीय वर्ष 2024- 25 के बाद के रिटर्न पर लागू होगा।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे हमें मामलों में फर्जी चालान के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि परिषद ने सभी कार्टन बक्सों और नालीदार तथा गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12त्न की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की। इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी... परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की कि फायर वॉटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा।

प्रमुख समाचार

नड्डा, मालवीय के खिलाफ जारी रहेगी जांच

नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को भारती जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक एनिमेटेड वीडियो के मामले में जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जेपी नड्डा ने मामला रद्द करने की याचिका दायर की थी। विचाराधीन मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। नड्डा और मालवीय के वकील ने तर्क दिया कि अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो भी इस तरह के मामले में राष्ट्रीय प्रमुखों को राज्य इकाई स्तर पर सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि इसी मामले के संबंध में एक और मामला अलग से दर्ज किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया कि दुश्मनी कैसे पैदा की गई।

100 दिन में मिशन इंडिया एआई लांच की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्र में मोदी सरकार 3.0 काबिज होने के बाद मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया है। सरकार में टेलीकॉम मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिली है। मंत्रियों ने कामकाज संभालने के बाद अब 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। टेलीकॉम विभाग अपने 100 दिनों के एजेंडे में प्राथमिकता के आधार पर स्पेक्ट्रम की सुचारू नीलामी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा टेलीकॉम एक्ट के नियमों जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कॉल और मैसेज इंटरसेप्शन और बायोमेट्रिक डाटा का स्टोरेज स्पष्ट होगा। टेलीकॉम विभाग के 100 दिनों के एजेंडे में टेलीकॉम नेटवर्क पर होने वाले फर्जीवाड़े को खत्म करना है। इसके लिए सरकार डाटा सेंटर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस को मजबूत करेगी। इसके अलावा डिजिटल सहमति को अनिवार्य करने की व्यापक व्यवस्था, ताकि बिना उपभोक्ता की मर्जी के कॉल, मैसेज उसके फोन तक नहीं जाएं। इधर, आईटी मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडा के तहत 30000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम सब्सिडी को मंजूरी संभव है।

हमारे नेता के सामने दिल्ली भी है नतमस्तकः कार्तिकेय

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने और दिल्ली जाने के साथ, राजनीतिक गलियारों में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के संभावित उत्थान को लेकर हलचल है। चौहान, जो अब केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ने पिछले रविवार को भोपाल में एक भव्य रोड शो का नेतृत्व किया। इसके बाद शुक्रवार को सीहोर के भेरुंदा में कार्यकर्ताओं का आभार सम्मेलन हुआ, इस बात की भारी चर्चा थी कि मंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान को उनके पिता द्वारा खाली की गई बुधनी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने शुक्रवार को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भेरुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। अलग-अलग दलों के नेता कार्तिकेय के बयान का वीडियो साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं दिल्ली में रहने के बाद हाल में ही लौटा हूं। पहले भी, हमारे नेता (चौहान) मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय थे। लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं रहने पर वह और लोकप्रिय हो गए।''

दिल्ली जल संकटः आपदा में अपने लिए अवसर खोज रहे नेता

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली शहर सरकार पर निशाना साधते हुए उसके मंत्रियों पर जल संकट को पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाने का अवसर बनाने का आरोप लगाया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में जीएनसीटीडी के मंत्रियों की तीखी बातचीत विभिन्न स्तरों पर चिंताजनक और संदिग्ध रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। एलजी ने कहा कि दिल्ली के राजनीतिक नेताओं ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से, पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपण करने के लिए संकट को अवसर में बदल दिया है। दिल्ली पीने के पानी की आपूर्ति उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है। अंतरराज्यीय जल-बंटवारे की व्यवस्था जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्र के माध्यम से तय की जाती है, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि इस ढांचे के तहत हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार राज्य पानी छोड़ने के लिए बाध्य हैं।

आरक्षण मुद्दाः शिंदे ने जातिगत तनाव नहीं फैलने देने का संकल्प जताया

नासिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समाज में जातिगत तनाव नहीं फैले। यह बात उन्होंने मराठाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा आरक्षण पर अपने रुख को मजबूत करने की पृष्ठभूमि में कही। शिंदे ने ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और अन्य को सरकारी हस्तक्षेप के बाद अनिश्चितकालीन अनशन वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया। शिंदे ने नासिक में संवाददाताओं से कहा, ''हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज में कोई जातिगत तनाव नहीं फैले।'' ओबीसी कोटा कम न किए जाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता हाके और नवनाथ वाघमारे 13 जून से अनशन पर थे। शनिवार को सरकारी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। मुंबई में शुक्रवार को ओबीसी नेताओं की बैठक की अध्यक्षता करने वाले शिंदे ने कहा कि 27 जून से शुरू हो रहे मानसून सत्र के पहले सप्ताह में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा, ''कल इस मुद्दे पर अच्छी चर्चा हुई थी।''

कैसे भारत सरकार को मालामाल सकता है यह लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर प्रचंड?

नई दिल्ली। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर प्रचंड के लिए 156 हेलीकॉप्टर्स का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इनमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को और 66 एलसीएच भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एलसीएच प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर मार्केट में निर्यात की नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। यह न केवल रेगिस्तानी इलाकों बल्कि हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे सियाचिन में भी अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है।

सेना को पांच से छह साल में मिलेंगे 156 प्रचंड

सरकार की मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को 156 हेलीकॉप्टर्स का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस आरईपी की अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये आने वाली है। वहीं इस खरीद से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की बढ़ेगी, बल्कि हथियारों के स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी तक एचएएल ने 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाए हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना के लिए दस और सेना के लिए पांच एलसीएच प्रचंड शामिल हैं। वहीं 156 हेलीकॉप्टरों के अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद इस ऑर्डर को पूरा होने में पांच से छह साल का वक्त लग जाएगा।

यूरोकॉप्टर टाइगर और अपाचे हैं पहुंच से बाहर

वहीं रक्षा विशेषज्ञ एलसीएच प्रचंड में बड़े निर्यात की संभावनाएं देख रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ और सेना से रिटायर्ड अधिकारी वत्स रोहित कहते हैं कि एलसीएच प्रचंड के बड़े प्रतिद्वंद्वी यूएस अपाचे और एएच-1जेड वाइपर जैसे पारंपरिक खिलाड़ी निस्संदेह ताकतवर हैं, लेकिन अपाचे की महंगी कीमत (30 मिलियन डॉलर से अधिक) और एएच-1जेड वाइपर की कीमत (20 मिलियन डॉलर से अधिक) के साथ ही, अमेरिकी विदेश नीति के चलते निर्यात पर लगी सीमाओं की वजह से उन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं है। वहीं अपाचे के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखे जाने वाले यूरोकॉप्टर टाइगर की कीमत 40 मिलियन डॉलर से अधिक है, जिसके चलते उसे खरीद पाना हर देश के बस में नहीं हैं। फ्रांस और स्पेन यूरोकॉप्टर टाइगर के अपग्रेड पर विचार कर रहे हैं, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया अपाचे ॥-64 से रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। जिसकी वजह से कई यूरोपीय देशों की निगाहें अब प्रचंड की ओर हैं।

रूसी हेलीकॉप्टर बेहद महंगे

रोहित कहते हैं कि वहीं रूस में बने एमआई-28एन और केए-52 (15 मिलियन डॉलर से 18 मिलियन डॉलर के बीच कीमत) भी ताकतवर टैंक रोधी हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन कम निर्यात और कम उत्पादन संख्या के चलते बाजार में उनकी पहुंच सीमित है। वहीं तकनीकी रूप से भी दोनों बहुत एडवांस नहीं हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध में अटैक हेलीकॉप्टर केए-52 की क्षमता दुनिया देख चुकी है, लेकिन यह काफी महंगा है। खुद रूसी सेना में भी इनकी संख्या 300 से कम है।

तुर्की और इटली के सहयोग से बने T129 ATAK की बात करें, तो इसकी कीमत 40 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। वहीं इसका प्रोडक्शन भी सीमित है। इसमें अमेरिका का दिया हुआ रुाङ्मश्वष्ट T800-4A इंजन लगा है। वहीं, चीन निर्मित मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर ‘-10श्व कीमत (17 मिलियन डॉलर से 20 मिलियन डॉलर के बीच) के मामले में तो प्रचंड के लगभग समान है, लेकिन एलसीएच प्रचंड इससे आगे है। वहीं, चीन का दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर ‘-19 और प्रचंड का वजन लगभग एकसमान है। हालांकि चीन ज्योपॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके हथियार बेचने के लिए लोन डिप्लोमेसी का सहारा लेता है, जो कई देशों को अखर सकता है। रोहित वत्स के मुताबिक एलसीएच प्रचंड की कीमत करीब 16 मिलियन डॉलर है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ लागत में कमी आने की पूरी संभावना है। वहीं प्रचंड अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। इसका कम वजनी डिजाइन इसे मुश्किल हालात में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। वह कहते हैं कि सेना जो मौजूदा प्रचंड इस्तेमाल कर रही है, उससे आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है। प्रचंड हेलिकॉप्टर्स से कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनेमी एयर डिफेंस, काउंटर इनसर्जेंसी ऑपरेशन, रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट को मार गिराने में आसानी होगी और हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस में मदद मिलेगी।

वत्स कहते हैं कि प्रचंड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी है, जो पश्चिमी देशों की जरूरत पूरा करती है। प्रचंड में फ्रांस में बना इंजन लगाया गया है, जिससे इसके निर्यात के लिए अमेरिकी की अनुमति लेनी जरूरी नहीं रह गई है। वह कहते हैं कि प्रचंड न केवल एंटी टैंक ऑपरेशन बल्कि बल्के हमलों और स्काउटिंग के लिए भी उपयुक्त है। इसके अलावा एलसीएच प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में यूरोकॉप्टर टाइगर की कमी को भी पूरा करता है। अगर हम इसे और कैपेबल बनाएं और इसकी लागत पर ध्यान दें>

भारत का नया कानून संबंधी सेमीनार

कई धाराओं में होगा बदलाव, एसपी भावना गुप्ता ने किया जागरुक

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पेंड्रा में भारत का नया कानून संबंध सेमिनार का जिला पुलिस के द्वारा आयोजन किया गया था। यह आयोजन पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, संजीव राय, सुचिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल, डीएसपी निकिता तिवारी, सहित जिले के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पेंड्रा के माधव राव सप्रे प्रेसक्लब के पत्रकार मौजूद थे कार्यक्रम का आयोजन माधव राव सप्रे प्रेस क्लब पेंड्रा में किया गया था।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि नई भारतीय न्याय संहिता-23 में पूर्व प्रचलित धाराओं व सजा प्रावधानों में कई बदलाव हुए हैं। उन्होंने उदाहरण से स्पष्ट किया कि हत्या के अपराध पर दर्ज होने वाली धारा-302 अब नए कानून के अनुसार धारा-103 के रूप में दर्ज होगी। साथ ही गैंगरेप की धारा-376(डी) की जगह अब नई संहिता के तहत धारा-70(1) के तहत अपराध दर्ज होगा। इसी तरह बलात्कार, जो कि भा.द.वि. के तहत धारा-376(3) के तहत दर्ज होता था, वह अब भारतीय न्याय संहिता में धारा-65(1) के तहत अपराध माना जाएगा।

चोरी धारा-378 की जगह अब धारा-303(1) के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। डकैती पर अब धारा-310(1), लूट पर अब धारा-309 के तहत अपराध दर्ज होगा। धोखाधड़ी पर धारा-420 की जगह अब धारा-318 के तहत जुर्म दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे कई धाराओं में परिवर्तन कर न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार कर अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान जमानत प्रक्रियाओं में सुधार, जांच व न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। वहीं संजीव राय के द्वारा नए कानून के तहत सजा प्रावधानों व डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मान्यता व साक्ष्य संबंधी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण के दिशा में किए गए प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि गंभीर प्रकरणों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नए कानून में मान्यता मिली है। भगोड़े अपराधियों पर कानून और भी सख्त बनाया गया है।

इन न्यायसंगत सुधारों से जहां छोटे अपराधों में लिप्त आरोपियों को सुधरने का अवसर दिया गया है, वहीं जघन्य अपराधों पर कड़ी सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार कम्युनिटी सर्विस जैसी सजा का प्रावधान कर अपराधियों को सुधरने का भी अवसर दिए जाने का प्रावधान है। न्याय संहिता में ई-एफ.आई.आर. का प्रावधान है, जिसमें तीन दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थी को संबंधित थाने पर पहुंचकर अपनी पहचान, हस्ताक्षर सत्यापित कराना होगा।

वहीं डीएसपी निकिता तिवारी ने बताया कि संशोधित नियमों व संहिता का गहन अध्ययन कर न्याय स्थापित करने व अपराधों की रोकथाम व पीड़ितों की मदद के लिए कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय संहिता की जानकारी देने नियमित कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।। साथ ही सभी ने 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू होने वाले नए कानून %%भारत न्याय संहिता%% के संदर्भ में विषय विशेषज्ञों के द्वारा नए कानून की बारीकियों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा और जानकारी दी गई थी।

आईजी झा ने रेलवे सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश, बोले-

सीमा विवाद में मत उलझें, पटरी से तत्काल निकलवायें शव

राजनांदगांव। राजनांदगांव रेंज आई.जी. श्री दीपक कुमार झा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव के सभागार में रेलवे सुरक्षा समिति का समीक्षा बैठक ली गई जिसमें पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनंदगांव राहुल देव शर्मा, आरपीएफ डोंगरगढ़ निरीक्षक, प्रशांत अन्डक, जीआरपीएफ डोंगरगढ़ उप निरीक्षक हरिश शर्मा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी प्रभारी (जी.आर.पी.) राजनंदगांव मनोहर राव ठाकरे, एवं थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक सी.आर. चंद्रा, उप निरीक्षक थाना कोतवाली राजनांदगांव धनीराम नारंगे मौजूद रहें।

आई.जी. दीपक कुमार झा ने पटरी पर शव मिलने की स्थिति में किसी भी तरह के सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए पुलिस को अहम निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा है कि पटरी पर शव की सूचना पर तैनात पुलिसकर्मी तत्काल आवश्यक बंदोबस्त करें। साथ ही जीआरपी व आरपीएफ के समन्वय से आगे की विधिक प्रक्रिया को पूरा कराया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसी किसी भी स्थिति में रेल का आवागमन बाधित न हो। सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर अधिक सतर्कता बरते जाने की बात कहते हुए उन्होने रेल्वे स्टेशनों में मादक पदार्थों एवं मानव तस्करी रोकथाम हेतु जी.आर.पी., आर.पी.एफ. एवं जिला बल के साथ संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही करने का

निर्देश दिया। उन्होने रेल्वे कॉलोनियों एवं स्टेशन के आस-पास असामाजिक तत्वों का स्वाभाविक जमावड़ा के मद्देनजर अपराध घटित होने की प्रबल संभावना की आशंका बताते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्र चिन्हांकित कर जिला पुलिस बल एवं रेल्वे पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा युवक/युवतियों को रेल्वे के माध्यम से नौकरी दिलाने मजदूरी के नाम से एवं अन्य कार्य हेतु बाहर ले जाते है। मानव तस्करी की घटना को रोकने हेतु जी.आर.पी., आर.पी.एफ. एवं जिला पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम बनाकर ऐसे प्लेसमेंट एजेंसियों की गतिविधियों पर सतत् निगाह रखते हुये उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें रेल्वे स्टेशन में किसी अप्रिय बड़ी घटना की स्थिति से निपटने के लिये जी.आर.पी., आर.पी.एफ.एवं जिला पुलिस बल व रेल्वे के रिस्पांस टाईम आदि पर ध्यान रखने हेतु मॉक ड्रिल आवश्यक रूप से कराया जावें।

इस तरह की कार्यवाही समय-समय पर किये जाने से आकस्मिक घटना घटित होने की स्थिति में कर्तव्यस्त् अधिकारी/कर्मचारियों को अपने-अपने दायित्वों के अनुसार कार्यवाही करने में सुविधा होगी। रेल्वे संपत्ति की चोरी की वारदात रोकने हेतु रेल्वे लाईन में नियमित रूप से गश्त एवं पेट्रोलिंग कराया जावें। रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वारों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। प्लेटफार्म में सीसीटीवी कैमरे प्राथमिकता के आधार पर लगवाये जाये। साथ ही यहां ड्यूटी करने वाले कर्मचारी से फीडबैक लेते रहें। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों व उनके सामानों की चेकिंग के लिए लगे सुरक्षा-उपकरणों को भी देखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी उपकरण चालू हालत में हो। ट्रेन एवं रेलवे स्टेशन में मोबाइल चोरी रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने एवं अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियत्रंण के लिए त्वरित कार्रवाई करने निर्देश दिया गया साथ ही रेलवे स्टेशन के आसपास नशा का सामान परिवहन करने वालों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने व नशा करने वालों को जागरूकता अभियान चलाकर समझाईस देने हिदायत दिया गया।

मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कर्मचारियों में भारी आक्रोश

कोरबा। आरोग्य केंद्र में काम करने वाले सामुदायिक चिकित्सा कर्मचारियों ने तीन मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल में कोरबा जिले के सभी केदो को मिलाकर 170 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। उनकी हड़ताल से संबंधित केंदों पर आधारित चिकित्सा सुविधा सेवाओं पर असर पड़ा है। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगी।

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वैलनेस सेंटर में इन सभी कर्मियों को पिछले वर्षों में सेवा करने का मौका दिया है। कोरबा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे ऐसे वैलनेस सेंटर में कर्मचारियों की संख्या 170 के आसपास है, जो अपनी तीन मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इनमें महिला पुरुष कर्मचारी शामिल हैं।

प्रदर्शन स्थल पर इन सभी ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि कार्य आधारित वेतन और 8 महीने का इंसेंटिव बकाया है। इन दो मांगों सहित एक अन्य मांग के लिए हमारा प्रदर्शन चल रहा है। निश्चित रूप से इस हड़ताल के कारण संबंधित केंद्रों से लोगों को मिलने वाली सेवाओं पर असर पड़ा है।

ओम प्रकाश चौहान ने ये भी बताया कि वेतन विसंगति और अन्य मांगे काफी लंबे समय से की जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी लापरवाही के कारण आज यह स्थिति निर्मित हुई है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा।

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एक पदाधिकारी ने बताया कि उनके एक सहयोगी पवन वर्मा को गलत जानकारी के आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया है। हमने सरकार से मांग की है कि उनकी बहाली जल्द कराई जाए।

हाईकोर्ट ने किए 10 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

■ रजिस्ट्रार जनरल बलराम वर्मा ने जारी किया आदेश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने 10 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं, साथ ही दो को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जारी आदेश के मुताबिक धमतरी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पंकज कुमार जैन को हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (चयन एवं भर्ती) नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट स्थापना में ओएसडी आदित्य जोशी को हाईकोर्ट की ई लॉ रिपोर्ट कमेटी के एडिटोरियल बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया है। यह आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार बालोद की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डॉ. प्रज्ञा पचौरी को इसी पद पर दुर्ग भेजा गया है। हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार (चयन एवं भर्ती) जितेंद्र कुमार को रायगढ़ का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाया गया है। स्थायी लोक अदालत, बिलासपुर के चेयरमैन मो. रिजवान खान को बैकुंठपुर का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाया

गया है। फैमिली कोर्ट, बिलासपुर के प्रिंसिपल जज श्यामलाल नवरत्न अब बालोद के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे।

हाईकोर्ट ने छह अतिरिक्त सेशन जजों के भी तबादले किए हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज प्रशांत पाराशर को बलौदा बाजार से दुर्ग, डॉ. ममता भोजवानी को सक्ती से कोरबा, विक्रम प्रताप चंद्रा को कोरबा से कोंडागांव और हाई कोर्ट में ओएसडी वीरेंद्र का रायगढ़ तबादला किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज प्रशांत कुमार शिवहरे को सक्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट से सक्ती में ही प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और स्मिता रत्नावत को भाटापारा के फास्ट ट्रैक कोर्ट से भाटापारा में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल सेशन जज बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने फूंका आंदोलन का बिगुल

हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई

बीजापुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर राज्य के साथ साथ बीजापुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सीएचओ प्रकोष्ठ के बैनर तले शुक्रवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह पर चले गए हैं। जिससे जिले के दूरस्थ क्षेत्रों एवम ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई है।

अपनी तीन सूत्रीय मांगे जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का पिछले पांच महीनों से लंबित पीएलपी भत्ता नियमित रूप से प्रदान करने, शासन स्तर से गृह जिले में स्थानांतरण की छूट एवम मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूरी में निवासरत होते हुए कार्य करने मंजूरी के साथ साथ कांकेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक की बहाली की मांग आदि शामिल है।

इससे पूर्व तीन दिवस तक ऑनलाइन एंट्री का कार्य पूर्ण रूप से बंद कर सांकेतिक रूप से शासन को सूचना दे दी गई थी। किंतु शासन स्तर से कोई कार्यवाही ना होता देख सभी सीएचओ ने आंदोलन का रुख अपनाया है। 21 तारीख से चल रहे इस आंदोलन में सभी कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति देखी जा रही है। उक्त आंदोलन में सामुदायिक प्रकोष्ठ की जिला संयोजक मयूरी देवांगन सहित गीतेश्वरी नेताम, शारदा मंडावी, प्रभा साहनी, साधना मिश्रा, अनिता नाग, ममता पांडे, कुलेश्वरी नेताम, कशिश झाड़ी, लोकेश आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

प्रदीप मिश्रा के कथा के दौरान पाकिटमारी, 3 महिला गिरफ्तार

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। गंडई में अंतरराष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा इन दिनों चल रहा है और कथा सुनने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ पाकिटमार गिरोह सक्रिय भी है। लेकिन पुलिस की तगड़ी निगरानी के कारण पाकेटमार गिरोह के एक पुरुष व 3 महिला आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आदतन बदमाश पाकेटमार गिरोह के सदस्य गंडई नगर में चल रहे शिव महापुराण कथा के पंडाल के आसपास पाकेटमारी की घटना कारित करने घूम रहे हैं। सूचना पर सायबर टीम द्वारा श्रद्धालुओं का पाकेटमारी करने की कोशिश करने वाले अजीत सौरा (19) पंडरिया, वनिता मोरे (35), सनिता सोनटेके (40) एवं प्रियांशी कामले (45) सभी खेड़ागांव नागपुर निवासी को पकड़कर थाना लाकर चारों व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।

तालाब को पाटना पड़ा महंगा मालिक समेत 6 पर अर्थदंड

तखतपुर। क्षेत्र के ग्राम सागर में तालाब को पटवाना खुद ही तालाब मालिक को मंहगा पड़ गया। निजी तालाब को पाटकर खेती करने वाले तालाब मालिक समेत 6 लोगों पर एसडीएम ज्योति पटेल ने 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया है। साथ ही निजी तालाब की भूमि को तालाब के स्वरूप में प्रवर्तित करने का आदेश जारी किया। दरअसल निजी तालाब में ग्रामीण निस्तारी करते हैं। इसे पाटने पर ग्रामीणों ने तालाब मालिक महेंद्र तिवारी सहित 6 लोगों के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी। यह मामला तखतपुर राजस्व कोर्ट में पिछले दो साल से चल रहा था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने एसडीएम तखतपुर को जांच के आदेश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच में वर्तमान खातेदार सहित 6 लोगों द्वारा तालाब को पाटा जाना पाया गया। इसके बाद एसडीएम ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 लोगों पर 25-25 हजार अर्थदंड का आदेश जारी किया।

आयुष पॉलीक्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

राजनांदगांव। आयुर्वेद विभाग द्वारा शासकीय आयुष पॉलीक्लिनिक राजनांदगांव में ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य मस्कुलोस्केलेटल विकार संबंधित व्याधियों के प्रति जागरूकता, रोकथाम एवं निदान चिकित्सा के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ शिल्पा पाण्डेय ने बताया कि शिविर में जिले में संचालित आयुष राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के विषय में जानकारी दी गयी। आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डॉ. प्रज्ञा सक्सेना ने नागरिकों को ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य मस्कुलोस्केलेटल विकार से होने वाली व्याधियों के कारण, लक्षण, बचाव एवं उपाय के विषय में जानकारी दी। योग चिकित्सक डॉ. भारती यादव द्वारा योगाभ्यास कराया गया एवं योग परामर्श दिया गया। जोड़ो एवं अस्थिपेशी रोगों हेतु आयुर्वेद चिकित्सा कार्यक्रम से सम्बन्धित शिविर में आयुर्वेद चिकिसधिकारी डॉ. सुनील भोई एवं डॉ. हर्ष कुमार, डॉ. प्रज्ञा सक्सेना ने चिकित्सा परामर्श दिया।

पौधरोपण के दृष्टिगत उद्योगों को कलेक्टर ने सौंपा दायित्व

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने पौधरोपण एवं जल संरक्षण के दृष्टिगत उद्योगों की बैठक ली एवं उन्हें दायित्व सौंपा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि जिले में व्यापक तौर पर पौधरोपण एवं जल संरक्षण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के लिए जनसहभागिता से मिशन जल रक्षा चलाया गया है। साथ ही पौधरोपण एवं जल संरक्षण के लिए उद्योगों का दायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 42 हजार पंप एवं बोरवेल के लगातार चलने से 85 प्रतिशत भू-जल का दोहन कर लिया गया है। जिसके कारण भू-जल स्तर में 18 मीटर की गिरावट आयी है। उद्योग अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए पौधरोपण एवं जल संरक्षण के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर पोधरोपण एवं जल संरक्षण के लिए अधिक कार्य करना होगा, जिसके परिणाम बाद में दिखाई देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सघन तौर पर पौधरोपण करने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी सघन पोधरोपण करना है।

माल लदान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देश में दूसरे स्थान पर

बिलासपुर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 236 मिलियन टन माल का लदान किया है जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 10त्न वृद्धि हुई है। माल लदान करने वाले जोन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। यह जानकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महाप्रबंधक सुश्री नीनु इटियेरा ने पत्रकारों के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे राष्ट्र का मालवाहक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे अधिक माल लदान करने वाला जोन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 236 मिलियन टन माल लदान किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने अपने रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशनों से 08 जोड़ी नई यात्री सेवाएं शुरू की हैं तथा 06 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया गया है। विभिन्न ट्रेनों को 16 स्टेशनों पर नए ठहराव दिए गए हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में 367 से अधिक अतिरिक्त कोच लगाए गए थे। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 32 अतिरिक्त कोच उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

कबीरधाम पहुंचा मानसून : जोरदार हुई बारिश, कई गांव हुए जलमग्न

■ पानी भरने से लोग परेशान

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में मानसून ने एंट्री कर ली है। मानसून के एंट्री होते ही जमकर बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां कृषि कार्य में अब तेजी आएगी तो वहीं निचले भाग में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल, बीती रात शुक्रवार को हुई बारिश के कारण जिले के ग्रामीण अंचल में निचली बस्ती में पानी भर गया है। पंडरिया ब्लॉक के ग्राम डोंगरिया खुर्द नवनिर्मित स्कूल भवन का परिसर में बारिश का पानी भर जाने से तालाब में तब्दील हो गया है। इसी प्रकार पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण ग्राम कोयलारी में भी पानी भर गया है। इससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।

वहीं बारिश को देखते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने प्राकृतिक आपदा से बचाव-राहत व बाढ़ से निपटने तथा संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा सहित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के विभिन्न विभाग के अधिकारियों को दिए है। कलेक्टर ने जिले के प्रमुख सकरी, हाफ, फोक नदी समेत जिले के सभी मध्यम जलाशयों के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़-आपदा प्रबंधन की आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों के लिए शासकीय भवन, पर्याप्त सुरक्षा स्थान और ऐसे पहुंच विहिन क्षेत्रों में जहां बाढ़ की स्थिति में पहुंचना संभव नहीं है, ऐसे स्थानों को चिन्हांकित कर वहां पर्याप्त मात्रा में खाद्य समाग्री, नमक, कोरोसीन, जीवन रक्षक दवाइयां आदि संग्रहित करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है। गौरतलब है कि कबीरधाम जिला वन व पहाड़ से घिरा हुआ है। वनांचल क्षेत्र में बारिश होने के कारण मैदानी क्षेत्र के नदी व नाले उफान पर रहते है। कवर्धा शहर से होकर गुजरने वाली सकरी नदी में बाढ़ का पानी आने लगा है।

बाढ़ आपदा नियत्रंण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

जिले में बाढ़ आपदा नियत्रंण कक्ष व कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का फोन नंबर 07741-232038 है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटा क्रियाशील रहेगा। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में इन फोन नंबर व अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। इन अधिकारियों में कवर्धा नगर पालिका सीएमओ नरेन्द्र वर्मा का मोबाइल नंबर 94077-60744, जिला नगर सेनानी व प्रभारी फायर बिग्रेड अधिकारी, पुलिस नियत्रंण कक्ष 07741-232674,231887,100 अथवा 112, जिला अस्पताल 07741-233553 अथवा 108 पर सूचना दी जा सकती है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

देवस्नान चंदन जात्रा पूजा विधान के साथ बस्तर गोंचा पर्व का हुआ शुभारंभ

जगदलपुर। रियासत कालीन बस्तर गोंचा पर्व में देवस्नान चंदन जात्रा पूजा विधान से शनिवार को शुभ मुहर्त में 12.30 बजे से प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा भगवान शालिग्राम को ग्राम आसना से श्रीजगन्नाथ मंदिर लाने की परंपरा के निर्वहन के बाद इंद्रावती नदी के महादेव घाट से पवित्र जल की पूजा उपरांत श्रीजगन्नाथ मंदिर लाया गया। तत्पश्चात शताब्दियों पुरानी परंपरानुसार भगवान शालीग्राम का पंचामृत, चंदन एवं इंद्रावती नदी के पवित्र जल से अभिषेक कर विधि-विधान से पूजा संपन्न किया गया।

इससे पूर्व प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र के विग्रहों को श्रीमंदिर के गर्भगृह में पूजा विधन के साथ आसन से उतारकर नीचे स्थापित कर देवस्नान चंदन जात्रा पूजा विधान संपन्न किया जाकर भगवान के 22 विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया किया गया। प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र के विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किये जाने के साथ ही भगवान का अनसर काल प्रारंभ होकर 5 जुलाई तक जारी रहेगा, इस दौरान प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र का दर्शन वर्जित होगा, 6 जुलाई को नेत्रोत्सव पूजा विधान के साथ प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता सुभद्रा एवं बलभद्र के दर्शन लाभ श्रृद्धालुओं को श्रीमंदिर के बाहर होगें।

360 घर आरण्यक ब्राम्हण समाज के अध्यक्ष ईश्वर नाथ खम्बारी ने बताया कि आज बस्तर गोंचा पर्व के 616 वर्षो की ऐतिहासिक रियासत कालीन परम्परानुसार देवस्नान चंदन जात्रा पूजा विधान संपन्न किया गया। इसके साथ ही बस्तर गोंचा पर्व प्रारंभ हो गया है। उन्होने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंदन जात्रा पूजा विधान के पश्चात भगवान जगन्नाथ का 15 दिवसीय अनसर काल की अवधि होती है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल से मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने की मुलाकात, प्रदेश की स्थिति पर हुई चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण

हरिचंदन से शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से कई अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा किए हैं। प्रदेश की वर्तमान स्थिति, खेती किसानी समेत कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सीएम साय का राज्यपाल से मुलाकात को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि साय कैबिनेट के मंत्री पद से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल में पुनर्गठन पर चर्चा हुई होगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही प्रदेश की स्थिति को लेकर चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रदेश के कई विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। इस मुद्दे पर भी सीएम ने चर्चा की है। सीएम साय ने राज्यपाल से मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि, आज राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें प्रदेश की वर्तमान स्थिति, कृषकों को खरीफ फसल के लिए खाद-बीज की उपलब्धता और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया।

साय मंत्रिमंडल में पुरंदर मिश्रा होंगे शामिल? कहा- रायपुर से एक मंत्री होना चाहिए

रायपुर। साय मंत्रिमंडल में दो मंत्रियों का पद खाली है। संभावित मंत्री के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही। शनिवार को राज्यपाल से सीएम विष्णुदेव साय के अलावा रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी मुलाकात की। रायपुर जिले से मंत्रिमंडल में जगह मिलने के सवाल पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा, मांग तो सभी 54 विधायक कर रहे हैं। राजधानी रायपुर से एक मंत्री होना ही चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। विधायक पुरंदर ने कहा, राज्यपाल से पारिवारिक संबंध है। उन्हें जगन्नाथ रथयात्रा का निमंत्रण देने राजभवन गया था। उन्होंने मंत्रिमंडल में खाली दो सीटों को लेकर कहा, बीजेपी के सभी विधायक मंत्रिमंडल के लिए प्रयास कर रहे हैं। मंत्रिमंडल दावेदारी के लिए नाम चर्चे में रहना ठीक है। रायपुर जिले से मंत्रिमंडल में जगह मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा, राजधानी रायपुर से एक मंत्री होना ही चाहिए।

आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से होगी शुरु

रायपुर। आरटीआई के तहत 1 जुलाई से शुरू होने वाले दूसरे चरण के आवेदन में आरक्षित सीट संख्या के हिसाब से ड्रा की प्रक्रिया किया जाएगा। आवेदन 30 जुलाई तक चलेगी। वहीं लॉटरी के लिए 17 से 20 जुलाई का समय निर्धारित किया गया है। लॉटरी के बाद 22 जुलाई से दूसरे चरण के चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया होगी।

70 लाख राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है। कुल हितग्राही 71,368 हितग्राहियों में से 71,145 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,167 हितग्राहियों में से 35,831 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला 78752 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है।

महतारी वंदन योजना बना रही महिलाओं को स्वावलंबी

रायपुर। महतारी वंदन योजना बना रही महिलाओं को स्वावलंबीछत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में लागू की गई महतारी वंदन योजना राज्य के महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रही है। योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत निर्णायक साबित हो रही है। योजना की सराहना अनेक जरूरतमंद महिलाओं के अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र के कर्मचारियों ने भी मुक्त कंठ से इसकी सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से आभार व्यक्त किया है। बालोद विकास खण्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 02 झलमला की कार्यकर्ता चन्द्रिका सिन्हा ने मिलने वाली राशि को जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बताया। उन्होने कहा कि समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग के अनेक महिलाएं जिन्हे अपने जरूरी तथा अनेक छोटे-बड़े आवश्यकताओं के लिए परिवार के मुखिया के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है।

बजट पूर्व बैठक में वित्तमंत्री चौधरी ने रखे राज्यहित के कई प्रस्ताव

वित्तमंत्री ने एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता का किया आग्रह

रायपुर। बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास व राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित राज्यहित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव व सुझाव रखे। दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री उपस्थित रहे।

बैठक में राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री श्री चौधरी ने भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने देश में अधोसंरचना निर्माण, कौशल संवर्द्धन, उद्यमिता विकास, और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, और जनसुविधाओं के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की भी प्रशंसा की है।

राज्यहित के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता के रूप में वर्ष 2020-21 से 50 वर्षों के लिये ब्याज रहित ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना के लिये गत वर्ष के समान ही 1,30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, किन्तु पार्ट-1 अंतर्गत गत वर्ष के प्रावधान 1 लाख करोड़ को कम करते हुए 55,000 करोड़ ही रखा गया है। उन्होंने इस योजना के लिए पूर्व की तरह राशि के प्रावधान का अनुरोध किया।

बैठक में स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत बताते हुए श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर अटल नगर को देश के सबसे सुनियोजित एवं ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के सीमित संसाधनों से सड़क, पेयजल, विद्युत सुविधा, आवास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है, किन्तु नई राजधानी को रायपुर तथा दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में आधुनिक नगरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है।

उन्होंने इसे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार की मांग करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण खदानों से खनिज का परिवहन पर्याप्त रेल नेटवर्क के अभाव में अधिकांशत: सड़क मार्ग से होता है। रेल द्वारा माल एवं यात्री परिवहन सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता होने एवं औद्योगिक विकास के लिए कारण रेल नेटवर्क का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार कार्यों की स्वीकृति का अनुरोध किया।

बैठक में वित्तमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की एक भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरती है। उन्होंने नागपुर-रायपुर-विशाखापटनम नवीन इंडस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित करने अथवा वर्तमान प्रस्तावित कॉरिडोर से रायपुर को जोड़ने की जरूरत बताई। इसके अलावा उन्होंने राज्य में टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का भी अनुरोध किया। वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दुर्गम वन क्षेत्रों में निर्मित सड़कों के संधारण हेतु बजट में प्रावधान करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंपों तक सड़क निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाए।

वित्तमंत्री ने रायपुर में वृद्धजनों के लिए इंटीग्रेटेड जिरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की दर और रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का आग्रह किया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत प्रीमियम राशि में वृद्धि करने की मांग की। श्री चौधरी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवें वेतनमान लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार का 50 प्रतिशत केंद्रान्श की मांग की। वहीं उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

वित्तमंत्री श्री चौधरी ने डीएमएफ के नए नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए डीएमएफ (जिला खनिज निधि) नियमों के अनुसार, डीएमएफ का उपयोग केवल खदान क्षेत्र के 15 किमी के भीतर या खदान से 25 किमी तक की दूरी पर रहने वाले लोगों पर ही किया जा सकता है। पहले के नियमों के तहत, डीएमएफ का 75त्न तक धनराशि उसी जिले में खर्च की जा सकती थी जिसमें खदान स्थित है, जबकि शेष 25त्न धनराशि पास के जिलों में भी खर्च की जा सकती थी। छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में कई नए जिलों का गठन हुआ है, जिससे आसपास के जिलों में विकास कार्यों के लिए डीएमएफ के धन को मिलाकर आवश्यकता के आधार पर खर्च करने की अधिक जरूरत है। लेकिन नए डीएमएफ नियम इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। खनन क्षेत्रों से सटे जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि की उपलब्धता के लिए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इस नियम को छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष्य में बदलने का आग्रह किया है, ताकि खनिज समृद्ध जिलों के आसपास के क्षेत्रों का भी समान विकास सुनिश्चित हो सके। इसके साथ वित्तमंत्री ने सभी आदिवासी विकासखंडों में एकलव्य विद्यालय स्थापित करने व आकांक्षी जिलों में दो नवोदय विद्यालय खोले जाने का आग्रह किया है।

बलौदाबाजार हिंसक घटना पर भड़के पूर्व सीएम बघेल

यह भाजपा सरकार का ही षड्यंत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना के बाद राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस-बीजेपी दोनों एक दूसरे को घटना की षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। दोनों एक दूसरे आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में भाजपा को घेरने का प्रयास किया है। उन्होंने जमकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व सीएम बघेल ने इस घटना को भाजपा सरकार की षड्यंत्र बताया है।

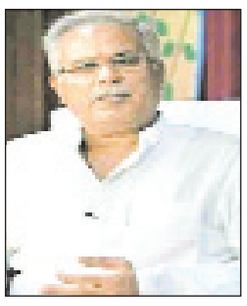

पूर्व सीएम भूपेश ने कहा कि बलौदाबाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस षड्यंत्र के तहत ही कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगी है। वहां खड़ी वाहनों में आग लगाई गई। अब जो जानकारी आ रही है वहां पुलिस द्वारा वाहन जलाए गए हैं। मारपीट की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी जो आवेदन दिए हैं, आयोजनकर्ता में से एक व्यक्ति है जिनके पिता हैं, उसके जीजा और उसके भाई सभी आए हुए हैं। उन्हें भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। उसको शाम के समय कलेक्ट्रेट परिसर में ले जाकर में उसे आकर्षित मुद्रा में उसे पत्थर मरवा रहे हैं। डंडा पकड़वा रहे हैं। उसे वीडियोग्राफी कर रहे हैं।

पूर्व सीएम भूपेश ने कहा कि दूसरी बात है यह है कि उन पर दबाओं डाला जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं का नाम लो। ऐसे में यह बेहद गंभीर मामला है। पूर्व सीएम बघेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार के देखरेख में सब कुछ हो रहा है। यह षड्यंत्र बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीजेपी सरकार का ही षड्यंत्र है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सफेद ध्वज लगाने वाले आरोपी की हुई गिरफ्तारी

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार कलेक्टर-एसपी कार्यालय परिसर स्थित ध्वजखंभ में सफेद ध्वजा लगाने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपित का नाम डिगेश्वर बांधे 21 साल निवासी कोरदा थाना लवन है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में अब तक 138 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि 10 जून को बलौदाबाजार में हिंसक घटना हुई, जिसमें उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में रखी सभी गाडिय़ों को आग के हवाले कर दिया था। आगजनी में पूरी सरकारी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने बलौदाबाजार में कलेक्टर कार्यालय के सामने ध्वजारोहण पोल पर सफेद ध्वज लगा दिया था। इस मामले में अलग-अलग नौ केस दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी की जा रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 22 सदस्यों की पुलिस एसआइटी गठित की गई है। उक्त टीम द्वारा आरोपितों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वीडियो, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तलाश जारी है।

सहकारी बैंक के दो अधिकारियों ने मिलकर 52 लाख रुपये का किया गबन

दोनों चढ़े पुलिस के हत्थे

रायपुर। राजधानी रायपुर में लाखों रुपये का गबन करने का मामला सामने आया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के दो अधिकारियों ने मिलकर 52 लाख रुपये गबन कर लिया। मामले में एफआईआर होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की खोजबीन कर गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है।

प्रार्थी शरद चंद्र गांगने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा प्रबंधक ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि बैंक की विजिलेंस सेल की ओर से 23 अगस्त 2023 को बैंक की शाखा सीओडी में निरीक्षण के दौरान शाखा में पदस्थ कनिष्ठ लिपिक चन्द्रशेखर डग्गर के बचत अमानत खाता और शाखा के सेवानिवृत्त सहायक लेखापाल अरूण कुमार बैसवाडे के बचत अमानत खाता का परीक्षण करने पर मासिक वेतन की राशि जमा होने के बावजूद अत्यधिक आर्थिक लेन-देन किया गया था। जांच में अरूण, चन्द्रशेखर और संजय कुमार शर्मा पूर्व सहायक लेखापाल शाखा सीओडी ने मिली भगत करके अनाधिकृत रूप से वर्ष 2017 से 2022 के दौरान विभिन्न तिथियों में शाखा के F- D- Interest Paid ,oa D-D- Interest Paid खातों को नामे (Debit) कर और अन्य खातेदारों के खातों से अत्याधिक राशि का आहरण करके आर्थिक अनियमितता कर बैंक को लगभग 52 लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई।

उन्होंने बताया कि अरूण कुमार बैसवाडे, चंद्रशेखर डग्गर और संजय कुमार शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान मिलीभगत कर विभिन्न खातों में गडबडी कर फर्जी तरीके से अपने-अपने स्वयं के खाते में बहुत बडी राशि जमा और आहरण कर अमानत में खयानत कर विभिन्न प्रकार की आर्थिक अनियमितता बरतते करीबन 52 लाख रुपये का गबन किया। मामले में एफआईआर होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी अरूण कुमार बैसवाडे और संजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी

अरूण कुमार बैसवाडे (66 साल) निवासी थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। संजय कुमार शर्मा (52 साल) निवासी जोरा पारा थाना मौदहापारा रायपुर।

फेल हुए छात्रों को दूसरी बार परीक्षा देने का मौका

रायपुर। छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में फैल हुए छात्रों के लिए एक और मौका है। इस सत्र से बोर्ड की मुख्य परीक्षा दो बार होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र-छात्राएं सामान्य शुल्क के साथ 21 से 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दो जलाई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। इस बार पूरक परीक्षा नहीं होगा। किसी भी विषय में फेल या श्रेणी सुधार करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। जिससे उन्हें दोबारा मौका मिल सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में दो बार अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर इसी सत्र से दूसरी बार मुख्य परीक्षा आयोजित कर रही है। इसमें वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हैं।

विद्यार्थी अनुत्तीर्ण और श्रेणी सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। इस बार सेकेंड चांस के लिए 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से और 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से शुरू होगी। माशिमं ने द्वितीय मुख्य परीक्षा हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को द्वितीय परीक्षा में भाग लेने के लिए तारीख निर्धारित कर दी है। ऐसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से या अवसर परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

352 श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आमचुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता हटने के बाद श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। मंत्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई है।

बता दें कि हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जल्द ही एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास या फिर नया घर खरीदने के लिए पात्र हितग्राही श्रमिकों को शासन की ओर से राशि दी जाती है। मंत्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है की इस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र श्रमिक हितग्राहियों को लाभ दिलवाएं।

पत्रकारिता जनसरोकार से दूर होती जा रही है : सुशील त्रिवेदी

■ प्रभाकर चौबे स्मृति संवाद श्रंखला का 7वां आयोजन संपन्न

रायपुर। प्रसिद्ध साहित्यकार, विचारक और संपादक प्रभाकर चौबे की छठवी बरसी पर आयोजित प्रभाकर चौबे स्मृति संवाद श्रृंखला के 7 वे आयोजन में वरिष्ठ साहित्यकार सुशील त्रिवेदी ने अपने उद्बबोधन् में कहा कि लोक हित और देश हित के लिए प्रारम्भ पत्रकारिता आज जन सरोकार से दूर होती जा रही है।

विदित हो कि प्रभाकर चौबे लगभग छह दशक तक पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े रहे। उनका व्यंग्य स्तम्भ हँसते हैँ रोते हैँ लगभग तीस वर्षो तक नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। फाउंडेशन के अध्यक्ष जीवेश प्रभाकर ने बताया कि प्रभाकर चौबे की स्मृति में प्रति वर्ष फाउंडेशन के तत्वावधान में व्याख्यान ,संवाद कार्यक्रम आयोजित् किया जाता है।

प्रभाकर चौबे फाऊंडेशन के तत्वावधान में संवाद श्रंखला का यह 7 वां आयोजन था। प्रारम्भ में प्रभाकर चौबे की पुण्यतिथि पर उन्हे पुष्पांजलि

अर्पित की गई एवं मुख्य वक्ता सुशील त्रिवेदी का आलोक चौबे एवं अध्यक्ष डॉ आलोक वर्मा का नंद कुमार कंसारी द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया।

इस वर्ष यह आयोजन पत्रकारिता पर केंद्रित किया गया था। व्याख्यान का विषय वर्तमान दौर में मीडिया की विश्वासनीयता और चुनौतिया था। वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुशील त्रिवेदी ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि इनफार्मेशन टेकनोलॉजी और ए आई के आधुनिक दौर में पत्रकारिता भी गंभीर रूप से प्रभावित है जिसकी चुनौतियों का सामना कल्पना शक्ति से ही किया जा सकता है। उन्होने पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तण्ड के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि 200 वर्ष पूर्व लोक हित और देश हित के सरोकार को लेकर प्रारम्भ पत्रकारिता आज जन सरोकार से दूर होती जा रही है। उन्होंने पत्रकारिता को लेकर महात्मा गांधी की चिंताओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि लगभग 100 वर्ष पूर्व ही महात्मा गांधी पत्रकारिता में गैरजिम्मेदार, अनर्गल , झूठे और भ्रामक समाचारों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे जो आज व्यापक रूप से हमारे सामने है । मुख्य वक्ता के रूप में श्री सुशील त्रिवेदी ने अपने संक्षिप्त मगर सारगर्भित उदबोधन् में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और चुनौतियों के सन्दर्भ में पेड़, फेक और नो न्यूज़ पर विस्तार से बात की।

कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि डॉ आलोक वर्मा ने अपने अध्यक्षीय उदबोधन् में पत्रकारिता की जमीनी सच्चाई पर अपने बात रखी। उन्होंने हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में मीडिया कवरेज , विभिन्न सर्वे और परिणाम को लेकर, विशेष रूप से अयोध्या और बनारस, के उदाहरण देते हुए जमीनी रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता पर अपनी बात कही।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 20/नि.शा./का.अ./लो.स्वा.यां./खण्ड, रायपुर, दिनांक 11.06.2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	कार्य का नाम	राशि (रू. लाख में)
1	पी एम श्री नवोदय विधालय माना कैम्प रायपुर में सम्पेवल कम पंप हाउस का निर्माण, पाईप लाईन बिछाने जोड़ने एवं सेन्ट्रीपयूगल पंप का स्थापना कार्य एवं अन्य सिविल कार्य (समस्त सामग्री सहित)।	17.67

उपरोक्त कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र कय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.06.2024 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
जी-242500478/3 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महासमुन्द

मैन्युअल पद्धति जोनल निविदा आमत्रंण सूचना क्रमांक- 2

क्रमांक / 02 / एस.ए.सी. / ग्रा.यां.से./2024-25 महासमुन्द, दिनांक 19/06/2024

एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु मैन्युअल जोनल निविदा आमत्रित की जाती है:-

क्र.	कार्य का नाम एवं स्थल	ठेके की अनु. लागत (लाख रू.) में
1	2	3
महासमुन्द जिले के प्रत्येक जनपद पचायतों मे सिविल कार्य हेतु		
1	जनपद पंचायत महासमुन्द / बागबाहरा / पिथौरा / बसना/ सरायपाली अन्तर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत रूपये 10.00 लाख से कम लागत के भवन, एवं अन्य निर्माण कार्यों का सम्पादन करना जिला महासमुन्द (प्रत्येक जनपद पंचायत हेतु निविदा राशि 20.00 लाख रूपये अलग-अलग होगी)	20.00 लाख
महासमुन्द जिले के प्रत्येक जनपद पचायतों मे विद्युतीकरण कार्य हेतु		
1	जनपद पंचायत महासमुन्द / बागबाहरा / पिथौरा / बसना/ सरायपाली अन्तर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत निर्माण कार्यों में रूपये 5.00 लाख से कम लागत के विद्युतीकरण के कार्यों का सम्पादन करना जिला महासमुन्द (प्रत्येक जनपद पंचायत हेतु निविदा राशि 10.00 लाख रूपये अलग-अलग होगी)	10.00 लाख

(टीप:- उपरोक्त कार्यों के निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 03/07/2024)

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारियों विभागीय वेबसाईड https://res.cg.gov.in में दिनांक 19/06/2024 से डाउनलोड की जा सकती है।

जी-242500491/4 कार्यपालन अभियंता

भारत के सामने मित्र बांग्लादेश को पास रखना चुनौती

महेंद्र वेद

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पंद्रह दिनों के भीतर दूसरी बार भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। पर यह इस पर भी निर्भर करता है कि भारत बांग्लादेश को क्या दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और हसीना, दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जटिल राजनीतिक व भू-राजनीतिक गतिशीलता से वाकिफ हैं, जिसमें क्वाड चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन को अलग-थलग करने के लिए भारत ऐसे प्रस्ताव देगा, जिन्हें वह आसानी से मना नहीं कर पाएंगी। इससे हसीना को अगले महीने चीनियों से बातचीत में भी कुछ लाभ मिलेगा। शेख हसीना ने चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित कर दिया है। भारत रक्षा पर 50 करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाइन का शीघ्र कार्यान्वयन चाहता है। हसीना ने तीस्ता नदी के विकास में वित्त पोषण और भागीदारी के चीन के प्रस्ताव को भी टाल दिया। समझौते के अनुसार, इसके पानी के समान बंटवारे की बांग्लादेश की पुरानी मांग है। लेकिन भारत इसे पूरा करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इससे सहमत नहीं है। इस बार भी समझौते की संभावना नहीं दिखती है। वर्ष 2026 में गंगा जल संधि खत्म हो जाएगी, जिसे परस्पर संतुष्टि के लिए फिर से नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यदि भारत इसमें चूक जाता है, तो चीन को बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की कोशिश करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए भारत को अपने 'सबसे करीबी' और 'मित्रवत' पड़ोसी की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश, दोनों के पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण हैं, जिसे पूरा करने के लिए सहयोग की जरूरत है। भारत 2047 तक 'विकसित' राष्ट्र बनना चाहता है और बांग्लादेश, 'स्मार्ट' राष्ट्र। आर्थिक विकास व सामाजिक सामंजस्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मनुष्यों (कथित अपराधियों समेत), मवेशियों, हथियारों और नशीले पदार्थों की सीमा पार अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। बांग्लादेश को भारत से ऋण की उम्मीद है। इसके लिए वह चीन से भी संपर्क करेगा। हालांकि हसीना की इस यात्रा के दौरान किसी नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है, पर ऐसी घोषणा संयुक्त विज्ञप्ति में की जा सकती है। भारत परस्पर लाभ के लिए निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का तेजी से क्रियान्वयन चाहता है। वर्ष 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7.36 अरब डॉलर का ऋण देने का वादा किया है। बांग्लादेश इस साल अप्रैल तक केवल 1.73 अरब डॉलर या वादे का 23 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया है। मौजूदा भारतीय क्रेडिट लाइन की शर्तें बहुत सख्त हैं। जैसे, हर परियोजना के लिए लगभग 65-75 प्रतिशत सामान या सेवाएं भारत से खरीदी जानी चाहिए, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। हसीना ने सोनादिया बंदरगाह को विकसित करने के चीनी प्रस्ताव पर कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत इसकी भरपाई करेगा। भारत एक नई द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और मोंगला समुद्री बंदरगाह में व्यापक भूमिका निभाना रहा है। हिंद-प्रशांत तक विस्तारित एक नया समुद्री मार्ग भी एजेंडे में है। इसके अतिरिक्त, भारत का लक्ष्य समुद्री सहयोग को बढ़ाते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में सागर परियोजना का विस्तार करना है।

सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर संशय

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी के लिये यह अच्छी खबर है कि हरियाणा-महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों और उत्तर प्रदेश में होने वाले उप विधान सभा चुनाव में भी सपा-कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा। इससे जहां यूपी में कांग्रेस को तो अन्य राज्यों में समाजवादी पार्टी को अपना विस्तार करने का मौका मिलेगा, इससे सपा को सबसे बड़ा यह हो सकता है कि उसको क्षेत्रीय की जगह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाये। इस रणनीति के साथ राहुल-अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं। अबकी से दोनों दलों का आलाकमान काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। इसीलिये यह भी तय किया गया है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन पर बात करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही अधिकृत होंगे, ताकि हाल में सम्पन्न मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसी तल्खी दोनों दलों के बीच दोबारा न पैदा हो। वैसे यह स्वभाविक भी था। क्योंकि इससे फायदा दोनों ही दलों को मिलेगा।

गौरतलब हो, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में कहा भी था कि यूपी के दो लड़के हिन्दुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनांएगे- खटाखट-खटाखट। इस बात को स्पष्ट संकेत माना जा रहा था कि कांग्रेस अन्य राज्यों के चुनाव में सपा को साथ रखने की इच्छुक है। अखिलेश की पीडीए रणनीति यूपी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। इस पीडीए रणनीति का विस्तार अब अन्य राज्यों में भी करने की सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है।

बता दें इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल की शुरूआत में दिल्ली और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा

चुनाव होने है। सपा महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा सीटों के लिए अपना दावा की कर रही है। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में उसके दो विधायक जीते थे। हरियाणा में भी करीब 20 सीटों पर मुस्लिम और यादव समीकरण प्रभावी है। सपा नेतृत्व चाहता है कि अन्य राज्यों में उसकी हिस्सेदारी बढ़े, ताकि उसे राज्य पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके।

बात उत्तर प्रदेश की कि जाये तो यहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने है, जिसमें 9 सीटें यहां के विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते खाली हुए हैं तो कानपुर की सीसामऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने से रिक्त हुई है। कांग्रेस पश्चिम यूपी के साथ-साथ पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीट है। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा कोटे की खाली हुई हैं तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा एक सीट आरएलडी और एक सीट निषाद पार्टी की है। यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक-दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है।

खैर, सीटों के बंटवारे की बात कि जाये तो कांग्रेस उपचुनाव में सपा से पांच सीटें मांग रही है, कितनी सीटों पर समझौता होता है यह तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। कांग्रेस की ओर से यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उप-चुनाव के लिए पांच सीटों का चयन किया है। फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा और गाजियाबाद सीट है। कांग्रेस के अंदुरूनी सूत्रों का कहना है कि वह सपा की 2022 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर हम दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि बीजेपी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों ने साफ कहा कि गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी में मीरापुर और खैर सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। पूर्वांचल की फूलपुर और मझवा सीट को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग की है। कांग्रेस पूर्वांचल और पश्चिमी दोनों ही इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है।

बता दें प्रयागराज की फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। इसी प्रकार अलीगढ़ की खैर सीट अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद चुनने के बाद खाली हुई हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी विधायक डॉ. अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने हैं। निषाद पार्टी के मिर्जापुर के मझवां से विधायक डॉ. विनोद कुमार बिंद अब भदोही बनने के चलते खाली हुई है। आरएलडी के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं।

राजनीति के जानकार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधान सभा उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन करके 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के मन के मुताबिक सपा सीट देने के मूड में नहीं है। सपा यूपी में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। सपा जो सीटें कांग्रेस को देने को तैयार है उसमें एक सीट अलीगढ़ की खैर और दूसरी गाजियाबाद सीट है। इसके अलावा सपा पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं दे रही है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-17)

गतांक से आगे...

जल का भेदन करने के बाद तेज (प्रकाश) को भेदता है, तेज का भेदन करने के पश्चात् वायु का भेदन करता है, वायु को भेदकर आकाश को भेदता है, आकाश को भेदकर मन का भेदन करता है, मन को भेदकर अहंकार का भेदन करता है, अहंकार का भेदन करने के पश्चात् वह महत्तत्व का भेदन करता है, महत्तत्व को भेद कर प्रकृति को भेदता है, प्रकृति का भेदन करने के पश्चात् वह अक्षर का भेदन करता है, अक्षर का भेदन करने के बाद वह मृत्यु का भेदन करता है और वह मृत्यु परमादिदेव परमात्मा में ही एक रूप रहती है। इस एकाकार के पश्चात् सत, असत् तथा सदसत् आदि कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार से यह निर्वाण (मोक्ष) का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन है, वेद की आज्ञा है? (यह अन्य किसी में ओत-प्रोत नहीं है) समस्त लोक आत्म स्वरूप परब्रह्म में माला के दानों की भाँति ओत-प्रोत हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा-जो पुरुष इन सभी लोकों की आत्मा में ही स्थित रहता है, वह आत्मस्वरूप ही हो जाता है। इस तरह यह निर्वाण (मोक्ष) विषय का अनुशासन है, यही वेद की शिक्षा है एवं यही वेद की आज्ञा है। इसके बाद रैक्व मुनि ने पुनः प्रश्न किया हे भगवन् ! यह विज्ञानघन आत्मा जब शरीर से उत्क्रमण करता है, तब किस जगह का परित्याग करके, किस रास्ते से बाहर की ओर प्रस्थान करता है? यह सुनकर घोराङ्गिरस ने कहना प्रारम्भ किया कि हृदय के मध्य भाग में मांस का लाल पिण्ड स्थित है। उस पिण्ड में चन्द्रमा के द्वारा विकसित होने वाले कमलिनी पुष्प की भाँति शुभ्र श्वेत एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म कमल विद्यमान है। उस सूक्ष्म कमल का विभिन्न तरह से विकास हुआ है। उसके मध्य में समुद्र स्थित है, इस समुद्र के बीच में कोश (स्थान विशेष) स्थित है। उसमें चार प्रकार की नाड़ियाँ-रमा, अरमा, इच्छा एवं अपुनर्भवा हैं। **(क्रमशः)**

राष्ट्रधर्म के जुझारु कर्मयोद्धा थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

ललित गर्ग

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक, राष्ट्रीयता के समर्थक और सिद्धान्तवादी थे। जब कभी भारत की एकता, अखण्डता एवं राष्ट्रीयता की बात होगी तब-तब डॉ. मुखर्जी द्वारा राष्ट्रजीवन में किये गए योगदान की चर्चा अवश्य होगी।

डॉ. मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झण्डा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमन्त्री (वजीरे-आजम) अर्थात् प्रधानमन्त्री कहलाता था। संसद में अपने भाषण में डॉ. मुखर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊँगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना जीवन बलिदान कर दूँगा। उन्होंने तात्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती दी तथा अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिये वे 1953 में बिना परमिट लिये जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ पहुँचते ही उन्हें गिरफ्तार कर नजरबन्द कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गयी। डॉ. मुखर्जी निरन्तर राष्ट्र श्रद्धा के प्रतीकों का मान एवं रक्षण करते रहे। वे सदैव देशहित में स्वदेशी चेतना, स्वदेशी जीवन पद्धति, स्वदेशी वेशभूषा तथा स्वदेशी संस्कार के प्रकटीकरण पर बल दिया। वे सच्चे अर्थों

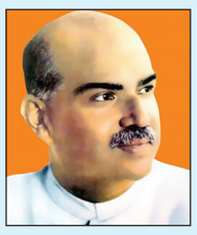

में राष्ट्रधर्म का पालन करने वाले साहसी, निडर एवं जुझारु कर्मयोद्धा थे। जीवन में जब भी निर्माण की आवाज उठेगी, पौरुष की मशाल जगेगी, सत्य की आंख खुलेगी एवं अखण्ड राष्ट्रीयता की बात होगी, डॉ. मुखर्जी के अवदानों को सदा याद किया जायेगा।

डॉ. मुखर्जी का जीवन बहुत संघर्षभरा रहा, अपनी राष्ट्रवादी नीतियों के कारण उन्हें बहुत से विरोध एवं उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनके अनुसार भारत कर्मभूमि, धर्मभूमि एवं पुण्यभूमि है, यहां का जीवन विश्व के लिये आदर्श है। भारत राज्य नहीं, सर्व प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है। इसे राष्ट्र बनाया नहीं, अपितु यह तो सनातन राष्ट्र है। डॉ. मुखर्जी द्वारा प्रदत्त महान् विचार एवं संकल्प तेजस्वी भारत राष्ट्र की परिकल्पना की सृष्टि करता है। डॉ. मुखर्जी में राजनीतिक शक्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रबल थी। वे निरन्तर भारत को शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाने के लिये प्रतिबद्ध रहे। यही कारण है कि वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिन्दू महासभा में सम्मिलित हुए। मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था। वहाँ साम्प्रदायिक विभाजन की नौबत आ रही थी। साम्प्रदायिक लोगों को ब्रिटिश सरकार प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिन्दुओं की उपेक्षा न हो। अपनी विशिष्ट रणनीति से उन्होंने बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया।

उत्तर कोरिया के बाद वियतनाम की यात्रा पर पुतिन

नीरज कुमार दुबे

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के अपने सफल दौरे के बाद जब वियतनाम की यात्रा पर पहुँचे तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के कान खड़े हो गये। दरअसल अमेरिका ने पूरी दुनिया में पुतिन को अछूत बनाने का प्रयास किया लेकिन पुतिन अपने विदेश दौरों के जरिये यह दर्शा रहे हैं कि वह हर जगह अब भी प्रभाव रखते हैं। भले उत्तर कोरिया पर पश्चिमी देशों की ओर से तमाम तरह के प्रतिबंध लगाये गये हैं लेकिन वियतनाम के साथ तो सबके अच्छे संबंध हैं इसलिए वहां पुतिन का स्वागत देख कर कई राष्ट्राध्यक्षों के होश उड़ गये। उत्तर कोरिया के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वियतनाम पहुँचे तो उनका वहां भी जोरदार स्वागत किया गया। एक सैन्य समारोह में रूसी राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी मिली। इसके बाद कम्युनिस्ट नेताओं ने गले लग कर रूसी राष्ट्रपति की भरपूर प्रशंसा की।

हम आपको बता दें कि पुतिन की वियतनाम यात्रा की अमेरिका और उसके सहयोगियों ने आलोचना की है और कहा है कि यूक्रेन पर युद्ध थोपने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का मंच नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इस सबसे बेपरवाह पुतिन अपना मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम द्वारा मास्को पर ताजा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस और वियतनाम ने ऊर्जा सहित अन्य मुद्दों पर समझौते किये। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रूस और वियतनाम के राष्ट्रपतियों की उपस्थिति में तेल और गैस, परमाणु विज्ञान तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में 11 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

रूसी मीडिया ने पुतिन के हवाले से कहा, हम वियतनाम के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं, जो रूस की विदेश नीति की प्राथमिकताओं में बनी हुई है। रूस की ञ्जस्स् समाचार एजेंसी ने राष्ट्रपति को यह कहते हुए उद्धृत किया कि दोनों देशों ने क्षेत्र में एक विश्वसनीय सुरक्षा ढांचा विकसित करने में रुचि दिखाई है। रिपोर्ट के अनुसार, अपनी यात्रा के समापन पर एक संवाददाता सम्मेलन में पुतिन ने नाटो सैन्य गठबंधन पर एशिया में रूस के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करने का आरोप लगाया।

इसके अलावा, एक अन्य कार्यक्रम में, वियतनामी राष्ट्रपति टू लैम ने कहा कि पुतिन ने सभी

कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करते हुए रूस का नेतृत्व करना जारी रखा, साथ ही क्षेत्र और दुनिया में शांति, स्थिरता और विकास में योगदान दिया। उन्होंने वियतनाम और रूस के साझा कम्युनिस्ट इतिहास का भी जिक्र किया। हम आपको बता दें कि हजारों वियतनामी कैडरों ने (जिनमें पोलित ब्यूरो के वर्तमान सदस्य भी शामिल हैं) ने पूर्व सोवियत संघ में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

जहां तक सवाल यह है कि पुतिन ने वियतनाम का दौरा क्यों किया तो इसके कई कारण हैं। दरअसल वियतनाम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा वह एक कम्युनिस्ट देश है। वियतनाम परिधानों का प्रमुख निर्यातक है और उसकी अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारी है। इसके अलावा वियतनाम भारत का बढ़ता रक्षा साझेदार है। साथ ही वियतनाम चीन के साथ संबंधों को संतुलित करने, बीजिंग के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाए रखने और एशियाई दिग्गजों से कथित सैन्य खतरों के खिलाफ पीछे हटने के दक्षिण पूर्व एशियाई प्रयासों का एक स्तंभ भी है।

वियतनाम की इन्हीं खासियतों के चलते पुतिन वहां पहुँचे। पुतिन को उम्मीद है कि उनकी वियतनाम यात्रा यह संकेत देगी कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस एशिया में अलग-थलग नहीं पड़ा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साल 2001 में रूस वियतनाम के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना था। रूस वियतनाम का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। दोनों देशों के बीच संबंध सोवियत संघ से चले आ रहे हैं। इसके अलावा, फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ प्रथम और द्वितीय युद्ध सहित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के दौरान सोवियत संघ का सैन्य समर्थन वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा था। इसके अलावा, शीत युद्ध के दौरान पूर्व सोवियत संघ हजारों वियतनामी छात्रों की मेजबानी करता था, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी के वर्तमान प्रमुख गुयेन फु ट्रोंग भी शामिल थे। यही नहीं, हनोई की वास्तुकला में सोवियत स्पर्श भी है।

जहां तक यूक्रेन युद्ध पर वियतनाम के रुख की बात है तो आपको बता दें कि साल 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से वियतनाम ने आधिकारिक तौर पर तटस्थ रुख अपनाया है। हम आपको बता दें कि वियतनाम और यूक्रेन, कभी सोवियत संघ का ही हिस्सा थे, इसलिए इनके बीच एक साझा इतिहास और कुछ हद तक सहानुभूति भी है। यूक्रेन भी वियतनाम को हथियारों की आपूर्ति करता था। कई वियतनामी लोग यूक्रेन में अध्ययन के लिए भी जाते थे। यही नहीं, वियतनाम ने युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से यूक्रेन को मानवीय सहायता भी प्रदान की है। फिर भी, वियतनाम पिछले सप्ताह यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पड़ोसी देश पर रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले चार प्रस्तावों पर भी अनुपस्थित रहा था। इसके अलावा वियतनाम ने मास्को को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने के खिलाफ भी मतदान किया था।

दूसरी ओर, वियतनाम में पुतिन का गर्मजोशी से किया गया स्वागत दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। दरअसल उत्तर कोरिया के संबंध तो पश्चिमी और कई एशियाई देशों से खराब हैं इसलिए वहां पुतिन का भव्य स्वागत हुआ तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन जब अमेरिका का करीबी देश वियतनाम भी रूस के राष्ट्रपति की जय जयकार करने पर उतर आया तो पश्चिमी देशों का चौंकना स्वाभाविक था। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल भारत यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन वियतनाम की यात्रा पर गये थे। वियतनाम का वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामरिक दृष्टि से काफी महत्व है इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वह रूस के साथ खड़ा हो जाये। अमेरिका को यह बात भी चुभी है कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के स्वागत के लिए जिस स्तर का समारोह आयोजित किया गया था उसी स्तर का स्वागत समारोह पुतिन के लिए भी आयोजित किया गया। यही नहीं पुतिन को वियतनामी राष्ट्रपति टू लैम और प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह दोनों ने गले लगाया था। हम आपको बता दें कि वियतनाम अमेरिका का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों ने पिछले वर्ष अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया था। पुतिन की हनोई यात्रा से विचलित अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक इस सप्ताह वियतनाम का दौरा करेंगे और स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता पर जोर देंगे। बयान में कहा गया है कि सहायक विदेश मंत्री डेनियल क्रिटेनब्रिंक अपनी यात्रा के दौरान एक मजबूत, स्वतंत्र, लचीले और समृद्ध वियतनाम के लिए अमेरिका के समर्थन की भी पुष्टि करेंगे। यही नहीं, अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि अमेरिका के साथ साझेदारी के लिए वियतनाम को रूस या चीन के साथ संबंध तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, वियतनाम में यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता ने कहा कि हनोई को अपनी विदेश नीति विकसित करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस के युद्ध ने साबित कर दिया है कि मॉस्को अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करता है।

बहरहाल, वियतनाम की विदेश नीति को विशेषज्ञ बैम्बू पॉलिसी कहते हैं। जैसे बांस जरूरत पड़ने पर इधर उधर झुक जाता है मगर उखड़ता नहीं वैसे ही वियतनाम की विदेश नीति जरूरत पड़ने पर लचीला रुख अपनाती है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा चीन के राष्ट्रपति ने भी वियतनाम का दौरा किया था और अब रूसी राष्ट्रपति वहां पहुँचे हैं। देखना होगा कि वियतनाम की विदेश नीति आगे क्या रुख लेती है?

आज का इतिहास

1894 बैरन पियरे डी कुबर्टिन की पहल पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पेरिस के सोरबोन में स्थापना।

1894 फ्रांसीसी इतिहासकार पियरे डी कूपर्टिन द्वारा पेरिस के सोरबोन में एक अंतरराष्ट्रीय प्रसंग का नेतृत्व करते हुए प्राचीन ओलंपिक खेलों को फिर से स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिकमिति की स्थापना की।

1919 स्वतंत्रता के एस्टोनियाई युद्ध-एस्टोनियाई सैनिकों ने चार दिन बाद क्षेत्र को फिर से तैयार करने के लिए लाटविया के सीसस के पास प्रो-जर्मन सरकार की स्थापना की।

1926 कॉलेज बोर्ड ने पहले SAT का संचालन किया, जो यूनाइटेडस्टेट्स में विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रवेश के लिए एक प्रमुख परीक्षण था।

1946 कनाडा का सबसे बड़ा तटवर्ती भूकंप, 7.3 मेगावॉट, मापने के लिए मारा गया, लेकिन वैंकूवर द्वीप, लेकिन केवल दो हताहतों का कारण बना, क्योंकि इसके उपरिकेंद्र के पास कई आबादी वाले क्षेत्र थे।

1956 जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए।

1956 गमाल अब्देल नासर मिस्र के राष्ट्रपति बने, एक ऐसा पद जो उन्होंने 1970 में अपनी मृत्यु तक कायम रखा।

1960 जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समौझाता हुआ।

1972 1964 के यूनाइटेड स्टेट्स सिविल राइट्स एक्ट के शीर्षक IX को किसी भी शैक्षिक प्रोग्रामरिंग फेडरल फंड्स में लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसने महिलाओं के खेल के छात्र एथलीटों में भारी वृद्धि की अनुमति दी थी।

1982 चीनी अमेरिकी विन्सेन्ट चिन की मौत अमेरिका के मिशिगन के हाईलैंड पार्क में अकोमा में पिटाई के बाद हो गई, दो ऑटोमोटिव वर्करों ने, जिन्होंने उसे जापानी के लिए हतोत्साहित किया था और जो जेजेओ ऑटो कंपनियों की सफलता को लेकर नाराज थे।

1991 वीडियो गेम सोनिक द हेजहोग को पहली बार रिलीज़ किया गया था, जिसमें सेगा उत्पत्ति 16-बिट कंसोल को बड़े पैमाने पर लोकप्रियता में बदल दिया गया था।

1991 सेज द हेजहोग वीडियो गेम श्रृंखला की पहली किस्त पहली बार जारी की गई थी, जिसने सेगा को एक अग्रणी गेम कंपनी में बदल दिया था।

1991 अफ्रीकी देश माल्दोवा ने आजादी की घोषणा की।

1996 शेख हसीना वाजेद ने बंगलादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

2012 एस्टन ईटन ने अमेरिकी ओलंपिक परीक्षण में डेक्थलान में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा।

1983 पोप जॉन पॉल द्वितीय ने पोलैंड के स्वतंत्र मजदूर संघ आंदोलन सॉलिडैरिटी के संस्थापक और नेता लेच वालेसा से निजी मुलाकात की थी। 1981 में पोलैंड में सामाजिक तनाव को देखते हुए मार्शल लॉ घोषित किया था और सॉलिडैरिटी पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था।

बाहरी बनाम उड़िया की जंग में खेत रहे नवीन पटनायक

उमेश चतुर्वेदी

साल 2000..संसद का बजट सत्र चल रहा था..मार्च के पहले हफ्ते का कोई दिन था..लोकसभा में मंत्रियों वाली सीट की ओर एक सांसद धीरे-धीरे बढ़ रहा था..उस शख्स को देख लोकसभा की प्रेस गैलरी में हलचल मच गई..इस हलचल पर नीचे बैठे कुछ सांसदों की निगाह पड़ी..उनकी भी निगाह उसी ओर चली गई, जिधर रिपोर्टर देख रहे थे..इस बीच तत्कालीन सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों की हथेलियां मेजों को थपथपाने लगीं..देखते ही देखते इस हथेली कोरस में समूचे सदन की हथेलियां जुड़ गईं..क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, हर सांसद की थपेली जैसे एक लय में मेजों को थपथपाने लगीं थी..इस कोरस में शामिल नहीं था, तो संसद के कर्मचारी और अधिकारी, जिन्हें नियम-कानून इसकी अनुमति नहीं देते..सांसदों के इस अभूतपूर्व स्वागत से उस शख्सियत का अभिभूत होना स्वाभाविक था..इस औचक घटना के बाद वह व्यक्ति विनम्रता से और भर उठा..

वह शख्सियत थे वाजपेयी सरकार के इस्पात मंत्री नवीन पटनायक...फरवरी 2000 में हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में उनकी अगुआई में बीजू जनता दल ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 68 सीटें जीत कर कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त कर दिया..अपने अस्तित्व के बाद बीजू जनता दल का वह पहला विधानसभा चुनाव था, जिसमें उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने 38 सीटें जीती थीं..तब उड़ीसा में नया इतिहास रचा गया। राज्य के कद्दावर नेता रहे बीजू पटनायक के इकलौते इंजीनियर बेटे के तूफान में बंगाल की खाड़ी के किनारे की धरती से कांग्रेस उड़ गई। तब नया इतिहास रचा गया था। उस जीत के नायक का लोकसभा में सम्मान के लिए अगर उस कांग्रेस के सांसदों को भी मजबूर होना पड़ा था, उसकी वजह सिर्फ जीत नहीं, बल्कि उस शख्स की सादगी और विनम्रता रही। यह विनम्रता विगत 13 जून को भी भुवनेश्वर में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखी, जब भूतपूर्व शासक के रूप में नवीन पटनायक शपथ मंच पर पहुंचे।

इसे संयोग कहें या कुछ और कि जिस बीजेपी की बैसाखी के सहारे नवीन पटनायक ने उड़ीसा में नया इतिहास रचा, उसी बीजेपी ने ठीक 24 साल बाद नवीन पटनायक को भूतपूर्व बना दिया। अठारहवीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मिले सदमे से जब बीजेपी जूझ रही थी, उसी वक्त उड़ीसा ने पार्टी को सांत्वना देने का काम किया। राज्य की 21 लोकसभा सीटों में बीस पर एकतरफा जीत हासिल करके राज्य को एक तरह से कांग्रेस मुक्त बना दिया। विपक्ष को मिली इकलौती सीट नवीन पटनायक को मिली।

इतिहास हमेशा विजेता का ही है। इस लिहाज से देखें तो आज के उड़ीसा का इतिहास बीजेपी का है। लेकिन सवाल यह है कि नवीन पटनायक ने गलती कहां की? नवीन पटनायक ने विवाह नहीं किया है। उनके पिता बीजू पटनायक पहले कांग्रेस में थे, बाद के दौर में वे जनता परिवार की अहम हस्ती रहे। जनता दल के नेता के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री बने। जब तक बीजू पटनायक जिंदा रहे, तब तक नवीन अमेरिका में इंजीनियर की नौकरी करते रहे। लेकिन उनके निधन के बाद नवीन ने नई पार्टी बनाई और बीजू पटनायक की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। 2000 के चुनावों में जिस बीजेपी के साथ वे सत्ता की सीढ़ी नापने में कामयाब रहे, उस बीजेपी से उन्होंने बाद के दिनों में अपना रिश्ता तोड़ लिया और देखते ही देखते उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय शख्सियत बन गए। यह लोकप्रियता बाद के हर चुनाव में दिखी, चाहे वह विधानसभा का हो

या लोकसभा का या फिर पंचायती चुनाव। लेकिन अपने आखिरी कार्यकाल में उन्होंने गलतियां शुरू की। तमिलनाडु मूल के आईएएस अधिकारी वीके पांडियन उनके करीबी बनकर उभरे। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पांडियन ने इस्तीफा दे दिया और बीजू जनता दल में नवीन के अघोषित उत्तराधिकारी के रूप में उभरते चले गए। उन्होंने चुनाव अभियान में खूब मेहनत की। उड़ीसा में यहां तक माना जाने लगा था कि आने वाले दिनों में अगर बीजू जनता दल को जीत मिलती है तो नवीन सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री होंगे और पांडियन असली मुख्यमंत्री होंगे।

जिस उड़ीसा के लोग पूरे देश में रोजगार और पढ़ाई के लिए फैले हुए हैं, जहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की तूती अमेरिका के सिलिकॉन वैली तक में बोलती है, उसी उड़ीसा के लोगों का अपना स्वाभिमान जाग उठा। उन्हें नवीन पटनायक तो पसंद रहे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में वी के पांडियन पसंद नहीं रहे। उड़िया बनाम बाहरी का नारा लगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसे जन नारा बना दिया। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी ने उस नवीन पटनायक को किनारे लगा दिया, जिन्होंने कभी उसका हाथ झटककर उसे किनारे लगा दिया था।

वी के पांडियन की पत्नी भी उड़ीसा में आईएएस अफसर हैं। सुजाता कार्तिकेयन और पांडियन की जोड़ी पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा प्रभावी हुई। उड़ीसा ऐसा राज्य है, जहां कम पढ़े लिखे, और कई बार अनपढ़ आदिवासी आबादी के साथ ही सवर्ण और पढ़े-लिखे प्रभावी लोगों का बेहतर अनुपात है। आदिवासी समुदाय में चर्चों का प्रभाव है। चर्च के प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद यहां गहरे तक सक्रिय है। संघ विचार परिवार के मजबूत सांगठनिक पहुंच और पकड़ के चलते देखते ही देखते बीजेपी ने भी गांव-गांव तक अपनी पैठ बना ली। नवीन पटनायक की चूंकि उम्र बढ़ रही है और वे शादीशुदा नहीं है। लिहाजा मौजूदा चलन के मुताबिक, उनकी विरासत को बढ़ाने के लिए उनके परिवार में कोई रहा नहीं। बीजू जनता दल का संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं रहा, लिहाजा वहां दूसरी पंक्ति का नेतृत्व उभर नहीं पाया। पांडियन और उनकी बढ़ती दखलंदाजी और प्रभाव के चलते बीजू जनता दल के कद्दावर नेता अलग होते चले गए। उनमें से ज्यादातर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस बीच बीजेपी ने आदिवासी समुदाय में अपनी पैठ बनाई। आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान कराया। चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता गया, बीजेपी ने स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को खूब उछाला। हालांकि शुरूआत में ऐसा नहीं लग रहा था कि नवीन पटनायक को बड़ी चुनौती मिल सकेगी। बड़े से बड़े राजनीतिक पर्यवेक्षक यही मान रहे थे कि बहुत होगा तो लोकसभा में बीजेपी की सीटें बढ़ जाएगी। विधानसभा में भी बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, लेकिन राज्य की सत्ता नवीन बाबू के ही हाथ रहेगी। लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे के साथ ही बीजू जनता दल के नेताओं के पलायन से उड़ीसा में संदेश गया कि अगर नवीन बाबू को जीत मिलती भी है तो उनके हाथ सत्ता नहीं रहेगी। उन पर शासन करने वाला उनका अपना नहीं, तमिलनाडु का नेता होगा। बीजेपी ने चुनाव अभियान में इसे बार-बार उछाला।

नवीन पटनायक 77 साल के हो गए हैं। उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता। राज्य में यह भी माना जाने लगा कि उनके स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल नहीं की गई। दबी जुबान से यह भी कहा जाता रहा कि उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली दवाएं दी गईं। बीजेपी ने तो अपने चुनाव अभियान में वादा तक किया कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह नवीन बाबू के स्वास्थ्य की उच्चस्तरीय जांच कराएगी। इससे पांडियन को लेकर रोष बढ़ा। जिसका नतीजा बीजू जनता दल की सत्ता से विदाई के रूप में सामने है।

अगर नवीन पटनायक ने अपने ही दल से अपना कोई उत्तराधिकारी चुना होता, दूसरी पंक्ति का नेतृत्व उभारने की पुरानी तैयारी किए होते तो शायद चुनावी नतीजे उनके लिए इतने खराब नहीं होते। सत्ता से बीजू जनता दल के बाहर होने के बाद माना जा रहा था कि राज्य में नेता प्रतिपक्ष का पद नवीन पटनायक वी के पांडियन को दे सकते हैं। हालांकि पांडियन ने बीजू जनता दल की हार के चलते राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ऐसे में लग रहा था कि नवीन पटनायक नेता प्रतिपक्ष का पद किसी और को भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंकाते हुए खुद को विधानसभा में विरोधी दल का नेता घोषित कर दिया है।

संदेहमुक्त चुनाव संवैधानिक अनिवार्यता

राजकुमार सिंह

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर विवाद थमते नहीं दिखते। दुनिया के बड़े अमीर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के मालिक एलन मस्क ने अब इसे अंतरराष्ट्रीय बना दिया है। मस्क ने 'एक्स' पर लिखा, 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनके इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा हैक किए जा सकने का खतरा है। हालांकि यह खतरा कम है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है.' दरअसल अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसमें वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच मुख्य मुकाबले के आसार हैं। मस्क ने यह टिप्पणी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखी। कैनेडी ने अपने पोस्ट में प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी धांधलियों के बारे में लिखा, 'प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग में कई अनियमितताएं सामने आईं। सौभाग्य से पेपर ट्रेल था, इसलिए उन्हें पहचान कर वोटों की गिनती को सही किया गया। सोचिए, जिन क्षेत्रों में पेपर ट्रेल नहीं हैं, वहां क्या होता होगा।' कैनेडी की पोस्ट और उसे रिट्वीट करते हुए मस्क द्वारा लिखी गई पोस्ट का संदर्भ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से है, लेकिन भारत में भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मस्क की इस टिप्पणी कि 'ऐसा कोई डिजिटल डिवाइस नहीं बन सकता, जो हैक या टैंपर न किया जा सके', को चुनौती देते हुए भारत की ईवीएम पर उन्हें ट्यूशन देने की बात तक कह दी। मस्क की जवाबी संक्षिप्त टिप्पणी आई कि 'कुछ भी हैक किया जा सकता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए टिप्पणी की कि 'भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है। किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है।' मस्क की टिप्पणी के बाद ईवीएम पर भारत में विवाद बढ़ने की आशंका इसलिए भी है, क्योंकि 2009 से ही उनकी विश्वसनीयता पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। जो भी दल विपक्ष में रहता है, वह इस पर सवाल उठाता है। चुनाव प्रक्रिया को संदेह से भी परे रखने के लिए जरूरी है कि सुधार-प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। वीवीपैट के शत-प्रतिशत मिलान से अगर संदेह का समाधान होता है तो उस दिशा में सोचा जाना चाहिए। चुनाव कोई टी-20 मैच नहीं, लोकतंत्र की प्राणवायु है। संदेह मुक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उनके परिणाम जल्द घोषित करने से कहीं ज्यादा जरूरी है।

भाजपा-आरएसएस : 'तूफान' गुजरने के बाद कायम हुआ सौहार्द्र!

हरीश गुप्ता

आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा (भाजपा) की 73 साल लंबी राजनीतिक यात्रा में आया अब तूफान थम गया है। अक्तूबर 1951 में शुरू हुए इस रिश्ते ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के तहत अपना स्वर्णिम युग देखा, क्योंकि इसके 'स्वयंसेवक' लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए देश पर शासन कर रहे हैं। लेकिन इस सौहार्द्र में तब खटास दिखी जब भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि पार्टी को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं है। हम अब सक्षम हैं। पहले हमें उनके (आरएसएस के) समर्थन की जरूरत थी, लेकिन अब नहीं नड्डा ने 21 मई, 2024 को लोकसभा चुनावों के दौरान यह बात कही। मोहन भागवत ने नड्डा द्वारा दिए गए इस असामान्य बयान का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह से अधिक समय तक इंतजार किया।

उन्होंने 4 जून को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जब भाजपा बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई और 11 जून 2024 को नागपुर में बोलने का फैसला किया। भागवत ने कहा, ''एक सच्चा सेवक कभी अहंकार नहीं दिखाता और हमेशा सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखता है।।। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादा का पालन करता है, जो अपने काम पर गर्व करता है।

फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित है - ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है।'' भागवत का संदेश जोरदार और स्पष्ट था। लेकिन जो लोग इस प्रकरण के लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद कर रहे थे, वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा को एहसास हो गया कि आरएसएस के बिना वह 'नई कांग्रेस' बनकर रह जाएगी क्योंकि यह दलबदलुओं से भरी हुई है। मोदी को भी एहसास हुआ कि 'संघ परिवार' सर्वोच्च है न कि 'मोदी का परिवार'। भागवत की नागपुर में दी गई नसीहत के कुछ दिनों के भीतर, आरएसएस के

तीन शीर्ष पदाधिकारियों ने मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन उम्मीद है कि नए भाजपा प्रमुख की नियुक्ति में आरएसएस की भूमिका बनी रहेगी और वफादार कार्यकर्ताओं का सरकार द्वारा ध्यान रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा वस्तुत: एक चुपचाप काम करने वाले अधिकारी हैं। लेकिन गुजरात कैडर के इस आईएएस अधिकारी को मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पसंद किया था। मोदी को काम करने वाले लोगों को परखने की ईश्वर प्रदत्त क्षमता प्राप्त है। पी.के। मिश्रा ऐसे ही लोगों में से हैं। जब मोदी गुजरात में थे, तब भी उन्होंने शरद पवार को विशेष रूप से फोन करके मिश्रा को दिल्ली में अच्छी पोस्टिंग दिलाने का अनुरोध किया था। पवार, जो कृषि मंत्री थे, ने उनकी बात मान ली और उन्हें कृषि सचिव नियुक्त कर दिया, जो दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे। जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तो मिश्रा को पीएमओ में उप प्रधान सचिव बनाया गया। नृपेंद्र मिश्रा मोदी के प्रधान सचिव थे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें राम मंदिर का तोहफा दिया। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया गया। यह अलग बात है कि वे हार गए। लेकिन ओडिशा के रहने वाले पी.के मिश्रा की राजनीतिक भूमिका भी रही है।

कहा जाता है कि आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने में उनकी भूमिका रही है। मुर्मु के चयन से न केवल ओडिशा बल्कि अन्य आदिवासी राज्यों में भी भाजपा को भरपूर लाभ हुआ। यह भी पता चला है कि मुर्मु ने केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू की जगह प्रतिष्ठित मयूरभंज लोकसभा सीट से भाजपा के नाबा चरण माझी के चयन में भूमिका निभाई थी। मुर्मु के कट्टर समर्थक माझी ने 1990 के दशक में उनके साथ काम किया था। पीके मिश्रा अक्सर उड़िया नौकरशाहों के साथ बातचीत करते थे और जमीन पर राजनीतिक स्थिति का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और चुपचाप भाजपा के लिए ओडिशा जीतने में अपनी भूमिका निभाई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 30 सदस्यीय मजबूत केंद्रीय मंत्रियों में से अश्विनी वैष्णव ही एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्हें तीन मंत्रालयों का प्रभार दिया गया है; रेलवे, आईटी और सूचना एवं प्रसारण। यहां तक कि चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान को भी कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिए जाने पर पंचायती राज मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा।

राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल को भी लोकसभा में चुने जाने के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा। उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से ही संतोष करना पड़ा। मोदी सरकार के एक और विश्वासपात्र भूपेंद्र यादव को श्रम एवं बेरोजगारी मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा। डॉ। मनसुख मंडाविया और धर्मेंद्र प्रधान का भी कद घटा। अश्विनी वैष्णव को तीन मंत्रालय मिलने के अलावा पार्टी के काम के लिए भी तैयार किया जा रहा है और वे किसी न किसी हिस्से में चुनाव की देखरेख में भूमिका निभा रहे हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वैष्णव को वित्त मंत्रालय सौंपा जा सकता है। लेकिन निर्मला सीतारमण इसलिए बच गईं क्योंकि भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें नहीं मिलीं और मोदी ने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वैष्णव पार्टी के घोषणापत्र के असली निर्माता थे, हालांकि घोषणापत्र समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी।

आघाड़ी के हौसलों के आगे गठबंधन पस्त

अमिताभ श्रीवास्तव

बीते बुधवार को दोनों शिवसेनाओं की जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब यह साफ दिखाई दे रहा था कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का जोश 'हाई' है। वह केवल पार्टी प्रवक्ता सांसद संजय राऊत के सुबह-सुबह होने वाले संवाददाता सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है उसके पास केवल टूटी हुई शिवसेना शिंदे गुट पर हमले का साहस ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मंच से बोलने की ताकत है। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई से लेकर बिना शर्त समर्थन देने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पर भी बिना नाम लिए कटाक्ष कर सकती है। वहीं दूसरी ओर वर्षगांठ मनाते समय शिवसेना शिंदे गुट अपनी पराजय को झुठलाने और अपने खिलाफ बनाए गए झूठे विमर्शों से आगे बढ़कर कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके पास कुछ आंकड़ों का आधार है, लेकिन वास्तविकता अभी जीत और हार की है। इस परिदृश्य में भाजपा हर तरफ से फंस कर अपने लिए कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढती नहीं दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव परिणामों में तीस सीटें जीतने के बाद महाविकास आघाड़ी के हौसले सातवें आसमान पर हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने शानदार विजय के बाद सीधे विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य सभी के सामने रख दिया है। अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है और कांग्रेस अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, फिर भी तीनों दल मिल कर पत्रकारों से मिल रहे हैं। कांग्रेस को अपनी जगह राष्ट्रीय स्तर से सक्रिय होने के निर्देश मिल रहे हैं। वह आंदोलनों का सहारा लेकर आम आदमी के बीच अपनी खोई जगह पाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी ओर राकांपा का शरद पवार गुट अपने से टूटे राकांपा अजित पवार गुट का उपहास बनाने में जुटा है और बार-बार निराशा परोसने के साथ अनेक विधायकों की 'घर वापसी' का शिगूफा छोड़ रहा है। शिवसेना का ठाकरे गुट तो महाराष्ट्र में आम चुनाव का खुद को 'हीरो' मान चुका है।

उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसने सीटें कितनी जीतीं, उसे इसका अंदाज भी नहीं लगाना है कि उसका निशाना सही कहां-कहां लगा। वह केवल इसी बात से खुश

है कि भाजपा तथा शिवसेना शिंदे गुट की चुनाव में पराजय हुई। जिसकी वजह पार्टी में फूट डालना रही। चुनाव बाद भी शिवसेना के ठाकरे गुट का आधा प्रलाप 'गद्दार' शब्द के नाम पर होता है, जिसके लिए उनके पास अब जीत का आधार है।

चुनाव में कथित तौर पर मिली सहानुभूति है। हालांकि दावों में यह भी कहा जा रहा है कि शिवसेना के ठाकरे गुट की सभी चालों का सीधा लाभ कांग्रेस और राकांपा शरद पवार गुट उठा ले गए। दूसरी तरफ भाजपा नीत महागठबंधन पूरी तौर पर 'बैकफुट' पर है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के अनेक बड़े नेताओं की पराजय के बाद राज्य नेतृत्व पर सवाल उठने की संभावना को भांपकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सरकार से त्यागपत्र देने का प्रस्ताव रखा। किंतु उसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया। मगर जब अपने सभी निर्णयों पर फड़नवीस खरे नहीं उतरे तो केवल 'वोट शेयर' समझा कर पराजय नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। माना जा सकता है कि अनेक स्थानों पर हार-जीत का फैसला कम मतों से हुआ, किंतु भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में कुल मत घटने से अंतर और भी कम हो सकता है। उस स्थिति में हार-जीत को केवल प्राप्त मतों के आधार पर तर्कसंगत नहीं बनाया जा सकता है।

आने वाले दिनों में राज्य की अनेक नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं में भी चुनाव होंगे, जहां मतों का अंतर और कम होगा। उधर, शिवसेना का शिंदे गुट भाजपा के 'चार सौ पार' के नारे को ही गलत मान बैठा है। वह उसे पराजय का एक कारण मान रहा है। महागठबंधन का एक तबका यह भी प्रचार कर रहा है कि मुस्लिम मतों का महाविकास आघाड़ी की तरफ एकतरफा झुकाव भी पराजय का एक कारण है। किंतु वह अगले चुनाव में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकसभा की एक सीट जीत कर राकांपा का अजित पवार गुट चुनाव के नतीजों के बाद अभी तक खुल कर सामने नहीं आया है।

हालांकि उसने इतना जरूर कहा कि पराजय के लिए उसके नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यद्यपि उसके कुछ नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दिख रहे हैं। उन्हें सीट बंटवारे की जल्दबाजी है। दरअसल 45 सीटें जीतने का ख्वाब लेकर चले महागठबंधन के सफर के 17 स्थान जीत कर ढेर होने से हताशा-निराशा हर तरफ है, जिसे कोई दबे शब्दों में व्यक्त कर रहा है तो कोई अप्रत्यक्ष अपनी भड़ास निकाल रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सारी बातों को अनदेखा कर राज्य इकाई को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। लेकिन जिन चिंताओं और समस्याओं के चलते उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, उनका समाधान अभी मिला नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) और मराठा दोनों ही समाज अपने-अपने आरक्षण के लिए आंदोलनरत हैं। बेरोजगारी की चिंता अब विद्यार्थियों की परीक्षाओं में हो रही अनियमितता से जुड़ गई है।

महंगाई के लिए कांग्रेस सहित विपक्ष शासित राज्य तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि राज्य में भाजपा नीत सरकार भी कोई तत्काल हल निकाल पाएगी। इस स्थिति में महाविकास आघाड़ी के पास आक्रामक होने के अवसर बढ़ जाएंगे, जो हाल के दिनों में दिख रहा है। बंटी हुई पार्टियों को लेकर मतदाता संभ्रम में पहले से ही है। जिससे आगे विधानसभा चुनाव में समीकरण अधिक जटिल होंगे। इसमें जो मतदाता को अपनी बात समझाने में सफल हुआ, वही विजेता बन जाएगा। फिलहाल महाविकास आघाड़ी की मस्ती के आगे महागठबंधन की सुस्ती ही है। आने वाले दिनों में विपक्ष के हौसलों की परीक्षा सत्ताधारियों की चुस्ती से होगी, जो लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद नेतृत्व के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती होगी।

सरकार-विपक्ष में टकराव से होगा नई लोकसभा का आगाज

दीपक कुमार शर्मा

नई लोकसभा की शुरुआत सरकार और विपक्ष के बीच टकराव से शुरू होगी। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में विपक्ष ने पेपर लीक सहित कई दूसरे मुद्दों पर एकजुट हो कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर के पद पर भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब के नियुक्ति को परंपरा की अनदेखी और टकराव मोल लेने की मानसिकता करार दिया है। गौरतलब है कि सोमवार और मंगलवार को नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री सदन को मंत्रियों से परिचित कराएंगे। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संयुक्त अभिभाषण और को 28 जून और एक जुलाई को दोनों सदनों में अभिभाषण पर चर्चा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दो जुलाई को लोकसभा तो तीन जुलाई को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल का प्रावधान नहीं रखा गया है। विपक्ष की योजना सोमवार को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर सवाल उठाने की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस आशय का संकेत देते हुए कहा कि नियुक्ति मामले में वरिष्ठता और परंपरा का उल्लंघन कर सरकार ने पहले ही दिन से टकराव मोल लेने का इरादा जाहिर किया है। नई लोकसभा में कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश और वीरेंद्र कुमार सबसे वरिष्ठ हैं। दोनों का यह आठवां कार्यकाल है। चूंकि वीरेंद्र मंत्री बन चुके हैं, ऐसे मं यह जिम्मेदारी सुरेश को दी जानी चाहिए थी। सरकार ने जिन भर्तृहरि महताब को यह जिम्मेदारी दी है, उनका बतौर सांसद यह सातवां कार्यकाल है। विपक्ष की रणनीति 28 जून को अभिभाषण पर चर्चा के दिन नीट यूजी और यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बहस की मांग करने की है। इंडी गठबंधन में शामिल दल इस दिन दोनों सदनों में कार्यस्थगत प्रस्ताव ला कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। जबकि सरकार की योजना इस विषय पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने वाले मानसून सत्र में चर्चा कराने की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को जल्द ही एक और नई जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता बनाने का फैसला किया है। इस आशय की आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। गौरतलब है कि पीयूष गोयल ने उत्तरी मुंबई सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें बीती सरकार की तरह ही इस सरकार में भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नड्डा के पास वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उनके पास भाजपा अध्यक्ष पद का भी दायित्व है। बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है।

सोनम पेरिस फ़ैशन वीक 2024 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी

सोनम कपूर, जो भारत में फैशन का अंतिम शब्द मानी जाती हैं, पेरिस में डियोर के हाउते कॉउचर फॉल/विंटर शो में शामिल होने के लिए जा रही हैं, जो की 24 जून को आयोजित होने वाला है। सोनम इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आमंत्रित होने वाली एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी हैं, जहां विश्व भर से फैशन के सबसे बड़े नाम शामिल होंगे। मीडिया द्वारा व्यापक रूप से ग्लोबल फैशन आइकन और पश्चिम के लिए भारत की सांस्कृतिक एम्बेसडर मानी जाने वाली सोनम, इस सुपर लक्जरी फैशन हाउस, डियोर के नवीनतम कॉउचर मास्टरपीस के अनावरण में मौजूद होंगी । सोनम ने पेरिस फैशन वीक, किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक, यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा आयोजित भारत-यूके रिसेप्शन और कान फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी स्टाइलिश उपस्थिति से वैश्विक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, जिसमें वह फ्रेंच रिवेरा में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थीं। हाल ही में, ईवनिंग स्टैंडर्ड द्वारा सोनम को पिछले दशक की यूके की सबसे बेहतरीन पोशाक पहने हुए में से एक माना गया था। सोनम ने प्रतिष्ठित टेट मॉडर्न म्यूजियम की साउथ एशिया एक्विजिशन कमेटी में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं।

कई प्रमुख वैश्विक फैशन इवेंट्स में, सोनम ने भारत और भारतीय कारीगरी का प्रतिनिधित्व करना सुनिश्चित किया है। उन्होंने अकेले ही भारत में फैशन को फोकस में लाया है। हाल ही में एक वैश्विक फैशन रिपोर्ट के अनुसार, सोनम उन हस्तियों की सूची में शामिल थीं जैसे ज़ेंडाया, काइली जेनर, केंडल जेनर, ब्लैकपिंक, बीटीएस आदि, जिन्होंने 2023 में लक्जरी फैशन ब्रांड्स के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था ।

किल में कमांडो की भूमिका के लिए लक्ष्य ने ली 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग

लक्ष्य अभिनीत फिल्म किल 5 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रीमियर पहले टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसकी मनोरंजक कहानी और जबरदस्त एक्शन दृश्यों के लिए इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि करण जौहर द्वारा समर्थित इस फिल्म में एक कुलीन कमांडो की भूमिका निभाने के लिए अभिनेता लक्ष्य ने एक व्यापक फिटनेस कार्यक्रम अपनाया था। पूरी कहानी पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें ।

हाई स्कूल में एक चैंपियन पहलवान रहे लक्ष्य ने एक्शन से भरपूर फिल्म किल में एक कुलीन कमांडो की भूमिका निभाने के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग अपनाया। 8-9 महीनों के दौरान, उन्होंने अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुश्ती की पृष्ठभूमि का उपयोग करते हुए गहन प्रशिक्षण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इस कठोर तैयारी ने न केवल उन्हें एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में आकार दिया, बल्कि भूमिका को प्रामाणिक रूप से निभाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए, लक्ष्य ने इस बात पर जोर दिया, 卐जब मैं 17-18 साल का था, तब मैंने इस पूरी यात्रा में एक पहलवान के रूप में शुरुआत की थी। मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ कुश्ती लड़ी और इस फिल्म के दौरान भी हमने लगातार आठ या नौ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो बेशक, इसमें बहुत प्रशिक्षण शामिल है। किल के नए रिलीज़ हुए ट्रेलर में तेज़ गति से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में जीवित रहने के लिए संघर्ष दिखाया गया है। लक्ष्य और उसकी गर्लफ्रेंड तान्या मानिकतला एक हथियारबंद समूह द्वारा किए गए एक भयानक हमले का सामना करते हैं, जबकि राघव जुयाल के खलनायक की भूमिका में आने से तनाव बढ़ जाता है। लक्ष्य एक सैनिक की भूमिका निभाते हैं जो हमलावरों से अपनी प्रेमिका की रक्षा करने के लिए लड़ता है।

यूथ को आकर्षित कर सकती है इश्क विश्क रिबाउंड

इश्क विश्क रिबाउंड प्यार, दोस्ती और वापसी की कहानी है । राघव पंडित (रोहित सराफ), सान्या (पश्मीना रोशन) और साहिर (जिबरान खान) देहरादून के बचपन के दोस्त हैं । सान्या और साहिर बड़े होने के बाद डेटिंग शुरू करते हैं । राघव उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शामिल है और हमेशा उनके लिए मौजूद रहता है । कॉलेज में उसकी मुलाक़ात रिया (नैला ग्रेवाल) से होती है और वह उससे प्यार करने लगता है । वह भी उसके लिए इमोशन फ़ील करती है और दोनों एक रिश्ते में बंध जाते हैं। रिया को इस बात पर संदेह है कि राघव सान्या और साहिर के लिए चौबीसों घंटे कैसे उपलब्ध रहता है । साहिर काम के लिए बाहर जा रहा है और सान्या इस बात से नाराज़ हो जाती है। वे एक ऐसे मोड़ पर पहुँच जाते हैं जहाँ वे अलग होने का फैसला करते हैं। हमेशा की तरह, राघव को एक एसओएस कॉल आती है, वह भी तब जब वह रिया के साथ इंटीमेट होने वाला होता है । रिया इस बात से नाराज़ होती है कि राघव उनका फ़ोन तब भी उठाता है जब वे प्यार करने के लिए तैयार होते हैं। वह उससे अलग हो जाती है। साहिर चला जाता है और रिया भी आगे बढ़ जाती है। इस बीच, राघव और सान्या एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। वे अपने रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। इस बीच, साहिर, जो उनके बीच क्या चल रहा है, इस बारे में अनजान है, वह सान्या के साथ सुलह करने की योजना बना रहा है। आगे क्या होता है, इसके लिए पूरी फ़िल्म देखनी होगी ।

डॉ. विनय छावल, वैशाली कमलाकर नाइक और केतन पेडगांवकर की कहानी आशाजनक है। डॉ. विनय छावल, वैशाली कमलाकर नाइक और केतन पेडगांवकर की पटकथा (आकर्ष खुराना और निपुण अविनाश धर्माधिकारी द्वारा अतिरिक्त पटकथा) में कुछ पल हैं। लेकिन यह कई जगहों पर गड़बड़ भी है, खासकर सेकेंड हाफ़ में। आकर्ष खुराना के डायलॉग संवादात्मक हैं ।

निपुण अविनाश धर्माधिकारी का निर्देशन ठीक है। उन्होंने फिल्म को हल्का-फुल्का पेश किया है जो काबिलेतारीफ़ है। इस क्षेत्र में हमें काफी समय से कोई फिल्म नहीं दिखी है और यह भी इस प्रोडक्ट के पक्ष में जाता है। उन्होंने कहानी में सहजता से गाने डाले हैं और कुछ दृश्यों में बेहतरीन काम किया है जैसे कि राघव द्वारा कुत्ते को चुराना, राघव का ब्रेकअप, राघव का जवाब खोजने के लिए इंटरनेट पर जाना आदि। इंटरवल से पहले के सीक्वंस अप्रत्याशित हैं।

लेकिन एक बार जब संघर्ष शुरू हो जाता है, तो फिल्म ऑफ़ ट्रेक हो जाती है। कहानी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सुपरसोनिक गति से आगे बढ़ती है। ऐसा भी लगता है कि निर्माताओं ने अवधि को नियंत्रित रखने के लिए कुछ दृश्यों को काट दिया। ऐसा करते हुए, फिल्म को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, दर्शक सान्या और उसके पिता के बीच के टूटे हुए बंधन को कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। साहिर का अपने पिता (शताफ फिगर) के साथ विवाद भी एक झटके के रूप में आता है, खासकर प्री-क्लाइमेक्स में। रिया का किरदार बेकार है। अंत में, क्लाइमेक्स किसी को भी प्रभावित नहीं करता है।

रोहित सराफ फिल्म की जान हैं। उनका क्यूट लुक और पपी आंखें उनके किरदार के साथ खूब जंचती हैं । अभिनय के लिहाज से, वे अव्वल दर्जे के हैं । पश्मीना रोशन शानदार लग रही हैं और उनमें संभावनाएं हैं । हालांकि, वह बहुत रॉ हैं और उन्हें अपने अभिनय कौशल को निखारने की जरूरत है, खासकर इमोशनल दृश्यों में। जिबरान खान ने आत्मविश्वास से भरपूर अभिनय किया है और शानदार प्रदर्शन किया है। नैला ग्रेवाल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन वह मुश्किल से ही वहां पहुंच पाई हैं। शताफ फिगर ने अच्छा साथ दिया है। कुशा कपिला मनोरंजक हैं। सुप्रिया पिलगांवकर (सान्या की मां) प्यारी हैं। आकाश खुराना (राघव के पिता) और शिल्पा विशाल शेट्टी (राघव की मां) ठीक-ठाक हैं। शीबा चड्ढा कैमियो में अच्छी लगी हैं।

रोचक कोहली का संगीत ठीक-ठाक है। इश्क विश्क प्यार व्यार, चोट दिल पे लगी और गोरे गोरे मुखड़े पे के रीक्रिएटेड वर्जन कारगर हैं। सोनी सोनी कानों को सुकून देने वाला है और इसे अच्छे से फिल्माया गया है। जावी ना अपनी छाप छोड़ने में विफल रही। केतन सोधा का बैकग्राउंड स्कोर ठीक-ठाक है। मिलिंद जोग की सिनेमैटोग्राफी ठीक-ठाक है, लेकिन लो-एंगल शॉट्स में यह अजीब लगती है। निखिल कोवाले का प्रोडक्शन डिजाइन आकर्षक है। अभिलाषा देवनानी और मनीषा मेलवानी की वेशभूषा ग्लैमरस है, लेकिन पश्मीना के मामले में बेवजह कमज़ोर है। अमृतपाल सिंह का एक्शन न्यूनतम है। चंदन अरोड़ा की एडिटिंग थोड़ी कटी-फ़टी है।

कुल मिलाकर, इश्क विश्क रिबाउंड में यूथ को आकर्षित करने की अपील है । लेकिन यह फ़िल्म कमजोर सेकेंड हाफ़ के कारण प्रभावित हो जाती है। बॉक्स ऑफिस पर, यह फ़िल्म संघर्ष करेगी ।

चंदू चैंपियन से कार्तिक आर्यन ने शेयर किया सबसे मुश्किल कुश्ती सीक्वेंस का बीटीएस वीडियो

इस समय सबसे एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स ड्रामस में से एक चंदू चैंपियन को हर तरफ से जबरदस्त रिव्यूज मिल रहें हैं।जहां एक तरफ ऑडियंस और फैंस ने मुरलीकांत पेटकर की रोमांचक दुनिया की खूब तारीफ की है, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन ने फिल्म के मेकिंग के समय का एक क्लास वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो दिखाता है कि कैसे इस शानदार फिल्म को बनाने के लिए एक्टर ने अलग-अलग चीजें करते हुए डेडीकेशन दिखाई है।

ऐसे में हमारे चैंपियन कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया पर एक क्लास वीडियो शेयर किया है, जो सच ने चैंपियन की डायरी है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए बताया है कि पूरी टीम ने इस फिल्म के लिए कितनी मेहनत की है और वह ही कभी हार नहीं मानने वाले इरादे के साथ ।

वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कार्तिक आर्यन ने फिल्म के लिए अपना बेस्ट दिया है, जिसमें उनके द्वारा किया गया बेहद मुश्किल कुश्ती सीक्वेंस भी शामिल है।

साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान द्वारा संग प्रोड्यूस की गई चंदू चैंपियन, अब बड़े पर्दे पर 14 जून 2024 को रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म अपनी दमदार कहानी और कार्तिक की जबरदस्त परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ रही है।

18 साल की उम्र में कास्टिंग काउच की शिकार, ईशा का छलका दर्द

ईशा कोप्पिकर कई साउथ फिल्मों में काम करने के बाद फिजा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में एक भयावह कास्टिंग काउच अनुभव के बारे में खुलकर बात की है। डरना मना है, पिंजर, एलओसी कारगिल, कृष्णा कॉटेज और डॉन जैसी फिल्मों में अभिनय करने के अलावा, ईशा कांटे से इश्क समुंदर और कंपनी से खल्लास जैसे विशेष डांस नंबरों का हिस्सा थीं।

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक साक्षात्कार में, इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों के दौरान कास्टिंग काउच के अपने अनुभव पर चर्चा करते हुए ईशा की आंखें भर आईं।

यह कभी इस बारे में नहीं था कि आप क्या कर सकते हैं। हीरो और एक्टर तय करते थे। आपने #MeToo के बारे में सुना होगा, और अगर आपके पास मूल्य थे, तो यह बहुत मुश्किल था। मेरे समय में कई अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री छोड़ दी। या तो लड़कियों ने हार मान ली या उन्होंने हार मान ली। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी इंडस्ट्री में हैं और हार नहीं मानी है, और मैं उनमें से एक हूं।

इस अनुभव को याद करते हुए ईशा ने कहा, मैं 18 साल की थी जब एक सेक्रेटरी और एक एक्टर ने कास्टिंग काउच के लिए मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझसे कहा कि काम पाने के लिए, आपको एक्टर्स के साथ 'दोस्ताना' होना चाहिए। मैं बहुत दोस्ताना हूँ, लेकिन 'दोस्ताना' का क्या मतलब है? मैं इतनी दोस्ताना हूँ कि एकता कपूर ने एक बार मुझसे कहा था कि थोड़ा रवैया रखो।

ईशा कोप्पिकर ने एक घटना भी बताई जब एक ए-लिस्ट एक्टर ने उनसे अकेले मिलने के लिए कहा। जब मैं 23 साल की थी, तो एक एक्टर ने मुझसे अकेले मिलने के लिए कहा, मेरे ड्राइवर या किसी और के बिना, क्योंकि उसके बारे में दूसरी अभिनेत्रियों के साथ संबंध होने की अफवाहें थीं। उसने कहा, 'मेरे बारे में पहले से ही विवाद हैं, और स्टाफ अफवाहें फैलाता है।' लेकिन मैंने मना कर दिया और उससे कहा कि मैं अकेली नहीं आ सकती। वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ए-लिस्ट एक्टर था।

ईशा ने उन दिनों को भी याद किया जब एक्टर्स और डायरेक्टर्स के सेक्रेटरी उन्हें अनुचित तरीके से छूते थे। उन्होंने कहा, वे आकर आपको अनुचित तरीके से नहीं छूते थे। वे आपका हाथ पकड़ते थे और गंदे तरीके से कहते थे, हीरोज के साथ बहुत दोस्ती करनी पड़ेगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अधीर रंजन ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से किया इनकार

कोलकाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन खबरों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के संविधान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चुनाव के बाद सभी प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष अस्थायी प्रमुख बन गए हैं। चौधरी ने कहा, मैं कांग्रेस की प्रदेश इकाई का अस्थायी अध्यक्ष हूं। जिस दिन से मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से भारत के किसी अन्य राज्य में अध्यक्ष नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि मीडिया ऐसी कहानियां गढ़ रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है तो वह ही क्षेत्रीय इकाइयों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। खरगे 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने किसी भी राज्य में अध्यक्ष नहीं बदला।

वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती हैं ममता

कोलकाता। चुनाव पूर्व मतभेदों के बाद तृणमूल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभवत: वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी केरल की उस सीट से चुनावी राजनीति में कदम रख रही हैं, जो उनके भाई राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में जीती थी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों से तीन लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र बरकरार रखा है। ममता बनर्जी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ा क्योंकि सीट बंटवारे पर असहमति के कारण उनके बीच मतभेद हो गया था। हालाँकि, दोनों पार्टियाँ राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक की छत्रछाया में सहयोगी बनी हुई हैं। दिसंबर में, बनर्जी ने सुझाव दिया था कि प्रियंका गांधी को वाराणसी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए।

विस चुनाव के लिए पवार मांगेंगे सीटों का बड़ा हिस्सा

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की सीट बंटवारे की वार्ता के दौरान सीटों का बड़ा हिस्सा मांग सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, पुणे में हुई एनसीपी की बैठक में मौजूद शरद पवार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों (सांसदों) से कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने गठबंधन के तहत कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार ने पार्टी नेताओं से कहा कि एनसीपी विधानसभा चुनाव के लिए सम्मानजनक संख्या में सीटों की मांग करेगी। पवार ने कहा कि वे आगामी चुनाव एमवीए के हिस्से के रूप में लड़ेंगे, इसलिए नेताओं को सावधान रहना चाहिए और कोई भी भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए जिससे ब्लॉक की एकता में बाधा उत्पन्न हो।

उत्तराखंड विस उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे आकाश आनंद

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने शुक्रवार को आगामी उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद उन नेताओं में शामिल हैं जो राज्य में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को होना है। मई में लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटा दिया था, उन्होंने ऐसी जिम्मेदारियों को संभालने में परिपक्वता की आवश्यकता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक वह परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और उत्तराधिकारी की भूमिका से मुक्त रखा जाएगा। आकाश आनंद ने मायावती को बहुजन समुदाय के लिए एक रोल मॉडल बताया और अपनी अंतिम सांस तक भीम मिशन और अपने समाज के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।

जगन मोहन रेड्डी का नई आंध्र सरकार पर तीखा हमला

अमरावती। आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को कथित अवैध निर्माण के कारण शनिवार सुबह नगर निगम अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस विध्वंस की निंदा की और कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना करते हुए इस विध्वंस को अंजाम दिया गया। उन्होंने राज्य में कथित अराजकता के लिए टीडीपी, भाजपा और जनसेना वाली एनडीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि यह विध्वंस इस बात का संकेत है कि अगले पांच वर्षों में नायडू का शासन कैसा होगा। रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चंद्रबाबू ने प्रतिशोध की राजनीति को अगले स्तर पर पहुंचा दिया। एक तानाशाह की तरह, उन्होंने खुदाई करने वाली मशीनों और बुलडोजरों से वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त करवा दिया, जो लगभग पूरा हो चुका था।

भारत-बांग्लादेश के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर

हम अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं: मोदी

नईदिल्ली। भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी की प्रधान मंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों और समझौतों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान मोदी ने सबसे पहले कहा कि पिछले 1 साल में हम 10 बार मिल चुके हैं, आज की मुलाकात एक विशेष मुलाकात है क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे तीसरे कार्यकाल में हमारी पहली राजकीय अतिथि हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो-पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है।

मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में हमने मिलकर जन कल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की हैं...दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में व्यापार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार मैत्री पाइपलाइन पूरी हो गई है। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली का निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग का पहला उदाहरण बन गया है। सिर्फ एक साल में इतने सारे क्षेत्रों में इतनी बड़ी पहल लागू करना हमारे संबंधों की गति और पैमाने को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की पहल की है। मैं दोनों टीमों को आज शाम क्रिकेट विश्व कप मैच के लिए शुभकामनाएं देता हूं... बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों टीमों को क्रिकेट विश्व कप मैच के लिए शुभकामनाएं देता हूं... बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

उन्होंने कहा कि हमने कनेक्टिविटी, वाणिज्य और सहयोग को अपना फोकस रखा है। पिछले 10 वर्षों में, हमने 1965 से पहले मौजूद कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया है। अब हम

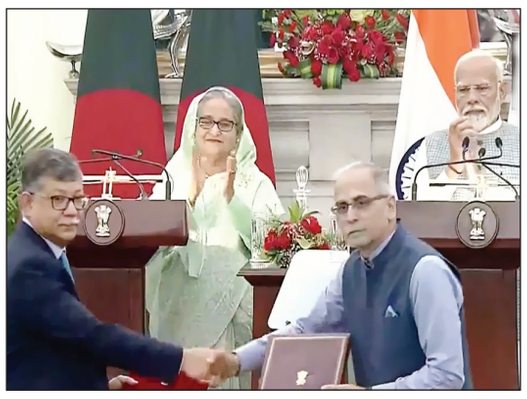

डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी. दोनों पक्ष हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सीईपीए पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने कहा कि 54 नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं - हमने बाढ़ प्रबंधन, प्रारंभिक चेतावनी और पेयजल परियोजनाओं पर सहयोग किया है। हमने 1996 की गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक तकनीकी टीम जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगी।

इस दौरान शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के 12वें संसदीय चुनाव और जनवरी 2024 में हमारी नई सरकार के गठन के बाद यह किसी भी देश की मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ हमारे संबंधों को बहुत महत्व देता है, जो 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान पैदा हुए थे... मैं भारत के उन बहादुर, शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण देती हूं।

बिभव कुमार को नहीं मिली राहत, 6 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

नईदिल्ली। नई दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 6 जुलाई तक बढ़ा दी। आप की राज्यसभा सांसद ने बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी।

विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी से उनकी अग्रिम जमानत याचिका बेकार हो गई है। 24 मई को, उन्हें चार दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

आतिशी के धरना स्थल पर जमकर हंगामा

नईदिल्ली। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने उस स्थान पर विरोध प्रदर्शन किया जहां दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जल संकट को लेकर अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखे हुए हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स अपनी नौकरी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आज, कुछ लोग मेरे विरोध स्थल पर अराजकता पैदा करने, अशांति पैदा करने, मुझ पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन मैं भाजपा को बताना चाहती हूं कि मैं गांधी जी द्वारा सिखाए गए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूं।

आतिशी ने कहा कि मैं नहीं चलूंगा इस तरह की चीजों से डरें। मैं ऐसे कार्यों से अपना सत्याग्रह समाप्त नहीं करने जा रही हूं।% जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को उनके वाजिब हिस्से का पानी नहीं मिल जाता, तब तक यह सत्याग्रह जारी रहेगा। मंत्री का अनिश्चितकालीन अनशन शुक्रवार को शुरू हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा यमुना नदी में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को हरियाणा ने 11 करोड़ गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) कम पानी छोड़ा।

उन्होंने कहा, ''एक एमजीडी पानी से 28,000 लोगों को जलापूर्ति होती है। 100 एमजीडी पानी की कमी का मतलब है कि दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।'' जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली को पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से नदियों और नहरों के जरिए उसे 1,005 एमजीडी पानी मिलता है जिसमें से हरियाणा 613 ??एमजीडी पानी मुहैया कराता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जारी भीषण गर्मी के बीच हरियाणा कुछ सप्ताह से 513 एमजीडी पानी ही दे रहा है जिस कारण 28 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं।

एमवीए में सीट बंटवारे पर अभी शुरू नहीं हुई बातचीत

मुंबई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाडी (एमवीए) के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी गठबंधन में सभी समान हितधारक हैं। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि एमवीए ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और दुनिया को यह दिखा दिया कि कैसे महाराष्ट्र ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोक दिया।

महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी में शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस घटक दल हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में एमवीए ने राज्य की 48 सीट में से 30 सीट पर जीत हासिल की थी। संजय राउत ने कहा, ''आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर अभी तक न तो राकांपा (एसपी) और न ही कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू हुई है। इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। सभी बराबर के हितधारक हैं।'' उन्होंने कहा, ''महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट हैं। किसी के लिए भी सीट की कमी नहीं होगी। सभी आराम से चुनाव लड़ सकते हैं।''

संजय राउत की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब राकांपा (एसपी) के एक नेता ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के हवाले से कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने एमवीए के घटक दलों की तुलना में कम सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी। राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राकांपा (एसपी) ने सबसे ज्यादा सीट जीतीं। वह 10 सीट पर चुनाव लड़कर आठ पर विजयी रही। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना (यूबीटी) ने 21 में से नौ सीट जीतीं, लेकिन विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमारी ही पार्टी को निशाना बनाया। राउत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) दो-तीन सीट मामूली मतों के अंतर से हारी है।

खेल
प्रमुख समाचार

गिलक्रिस्ट के स्तर तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा पंत को : स्मिथ

ग्रॉस आइलेट। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान स्मिथ का मानना है कि ऋषभ पंत की एडम गिलक्रिस्ट के साथ तुलना करना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भारत का विकेटकीपर बल्लेबाज अपनी वर्तमान फॉर्म को जारी रखता है तो वह ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी के करीब पहुंच सकता है। स्मिथ स्वयं भी विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं और पंत ने कार दुर्घटना से उबरने के बाद जिस तरह से वापसी की है उससे काफी प्रभावित हैं। पंत ने इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन किया और टी20 विश्व कप में भी वह विकेट के आगे और विकेट के पीछे अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभा रहे हैं।

पंत को वर्तमान समय में विश्व क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में गिना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक लगाए हैं लेकिन गिलक्रिस्ट की बराबरी पर पहुंचने के लिए उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना होगा जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15000 से अधिक रन बनाने के साथ 800 से अधिक कैच लिए हैं। टी20 विश्व कप में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे स्मिथ ने कहा,''ऋषभ पंत ने दुर्घटना के बाद दमदार वापसी की है और वह बेहतरीन फॉर्म में दिख रहा है। वह बेहद कुशल खिलाड़ी है। वह आक्रामक है, वह खतरनाक खिलाड़ी है।''

गिलक्रिस्ट की तरह पंत ने भी दिखा दिया है कि वह प्रत्येक प्रारूप में किसी भी क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। टी20 विश्व कप में उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा जा रहा है और उन्होंने अभी तक इस फैसले को सही साबित किया है। स्मिथ ने कहा,''वह किसी भी खिलाड़ी का अच्छी तरह से साथ निभा सकते हैं फिर चाहे वह विराट कोहली हो या रोहित शर्मा। इसलिए उन्हें तीसरे नंबर पर उतारने का फैसला सही है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बजट : सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की चर्चा

नईदिल्ली। देश 2024-25 के केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सरकार उस दिशा में तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए विधानमंडल सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से सुझाव लेने के लिए वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इस प्री-बजट बैठक का आयोजन किया गया था। भारत मंडपम में हुई बैठक में राजस्थान से दीया कुमारी और यूपी से सुरेश कुमार खन्ना सहित राज्य के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय इस समय बजट पर विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने की प्रक्रिया में है। वह अर्थशास्त्रियों, वित्त और पूंजी बाजार विशेषज्ञों और उद्योग निकायों से मिल चुकी हैं। पहली बजट पूर्व बैठक 19 जून को हुई थी।

अगले हफ्ते ओपन हो रहे 2 मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ

नईदिल्ली। साल 2024 आईपीओ के लिए सबसे शानदार सालों में एक रहने वाला है। इस साल अबतक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में ऑटो कंपनी ह्युंदै मोटर इंडिया है, तो वहीं भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक भी पब्लिक होने को तैयार है। हालांकि, इन सबसे पहले और अगले सप्ताह ही 10 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं और 11 आईपीओ की शेयर मार्केट लिस्टिंग होने वाली है। अगले सप्ताह यानी 24 जून से लेकर 28 जून के बीच में ओपन होने वाले आईपीओ में 2 मेनबोर्ड सेगमेंट के आईपीओ हैं और 8 एसएमई सेगमेंट के। अलाइड ब्लेंडर्स भारत में किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाली विदेशी शराब बनाने की कंपनी है। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली व्हिस्की इसी कंपनी की है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 25 जून को ओपन होगा और 27 जून को क्लोज हो जाएगा।

दो दिन में 43% उछला हेबाक कलोरेंट्स इंडिया का शेयर

नईदिल्ली। हेबाक कलोरेंट्स इंडिया के शेयरों ने इस सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शानदार बढ़ोतरी दर्ज की। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 19 फीसदी की उछाल के साथ 558 रुपये तक पहुंच गए थे। इससे एक दिन दिन पहले की उछाल को जारी रखते हुए जब क्वांट म्यूचुअल फंड ने कंपनी में ओपन मार्केट के जरिये 1 फीसदी से कम हिस्सेदारी खरीदी थी। पिछले दो ट्रेडिंग दिनों में, इस डाई और पिगमेंट कंपनी के शेयरों में 43 फीसदी की उछाल आई है। निफ्टी 50 शुक्रवार को 0.28% की गिरावट के साथ 23,501.10 पर बंद हुआ। हेबाक कलोरेंट्स इंडिया के स्टॉक ने 3 जनवरी, 2024 को 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 654.90 रुपये छुआ था। शुक्रवार को यह 8.30% की उछाल के साथ 508 रुपये पर बंद हुआ था। म्यूचुअल फंड ने इन शेयरों को एनएसई पर ब्लॉक डील के जरिये 453.57 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदा।

दिल्ली-नोएडा सहित कई शहरों में महंगी हुई सीएनजी

नईदिल्ली। सरकार ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 22 जून सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। सीएनजी की कीमत में एक रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद राजधानी नई दिल्ली में सीएनजी 74.09 रुपये की जगह 75.09 रुपये प्रति किलो मिलेगी। दिल्ली के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में सीएनजी महंगी हो गई है। इस बढ़ोतरी का असर एनसीआर क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहरों में सीएनजी की खुदरा कीमतों में पर पड़ने वाला है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में एक रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अभी तक सीएनजी 78.70 रुपये प्रति किलो के भाव पर मिल रही थी, जो अब 79.70 रुपये प्रति किलो हो गई है।

आरबीआई को अब ब्याज दरों में कटौती के बारे में विचार करना चाहिए

प्रह्लाद सबनानी

भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए इसे 6.50 प्रतिशत पर ही जारी रखा है। हालांकि, हाल ही में, जून 2024 के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न हुई मोनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की बैठक में दो सदस्यों ने रेपो दर को 25 आधार अंको से घटाकर 6.25 प्रतिशत पर नीचे लाने की सिफारिश की थी। अभी तक मोनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा लिए गए 48 निर्णयों में से 32 निर्णय सर्वसम्मत आधार पर लिए गए हैं और केवल 16 निर्णयों की स्थिति में ही कुछ सदस्यों द्वारा अपनी अलग राय रखी गई है। और, इस बार भी दो सदस्यों की राय अन्य सदस्यों की राय से कुछ भिन्न रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में मुद्रा स्फीति के सम्बंध में भी अपनी राय प्रकट की है और इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुद्रा स्फीति की दर 4.5 प्रतिशत पर बनी रहेगी और इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में मुद्रा स्फीति की दर 4.9 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही में 3.8 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में 4.6 प्रतिशत एवं चतुर्थ तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर में खाद्य पदार्थ सामग्री का विशेष योगदान रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। हालांकि, बाजार में खाद्य पदार्थ सामग्री की कीमतें यदि बढ़ती हैं तो इसे ब्याज दर बढ़ाकर अथवा घटाकर प्रभावित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बाजार में मांग एवं आपूर्ति के आधार पर ही निर्धारित होती हैं।

जैसे, सब्जी एवं फलों की आपूर्ति यदि बाजार में कम है और मांग अधिक है तो इन वस्तुओं की कीमतें बाजार में आसमान छूती नजर आती हैं और इन वस्तुओं की बाजार में यदि आपूर्ति बढ़ जाए तो इनकी कीमतें भी कम होने लगती है। अत: ब्याज दरों में वृद्धि अथवा कमी का इन वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव नगण्य सा ही रहता है। कुल मिलाकर, खाद्य पदार्थों की बाजार में आपूर्ति बढ़ाकर ही इन वस्तुओं की मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। और फिर, भारत में मुद्रा स्फीति की दर भी 4.5 प्रतिशत के आसपास ही बनी रही है जो मोनेटरी पॉलिसी में वर्णित 2.5 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत के बीच की सीमा के अंदर ही है। बैंक आफ कनाडा, स्विस बैंक एवं स्वीडिश रिस्कबैंक ने भी पूर्व में ही अपने अपने देशों की ब्याज दरों में कमी करने की सिफारिश की है। अत: क्या अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी रेपो दर में कमी करने के बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कमी संभवत: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा फेड दर में कमी को घोषणा के बाद की जाय, क्योंकि यदि भारत रेपो दर में कमी की घोषणा करता है एवं फेडरल रिजर्व फेड दर में कमी नहीं करता है तो इससे अमेरिकी डॉलर के रूप में पूंजी का भारत से पलायन हो सकता है। परंतु, हाल ही के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आंतरिक मजबूती के चलते ही अपने आर्थिक विकास को गति देने में सफल रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्य देशों के आर्थिक क्षेत्र में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने आर्थिक विकास की दर को 8 प्रतिशत से अधिक रखने में सफल रही है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में कमी करता है तो इससे भारत में उद्योग, कृषि एवं सेवा क्षेत्र को वित्त/पूंजी की उपलब्धता कम ब्याज दरों पर होने लगेगी, इससे इन क्षेत्रों में कार्य कर रही इकाईयों की उत्पादन लागत कम होगी एवं इनकी लाभप्रदता में सुधार होगा। जिससे अंतत: इन इकाईयों के विस्तार में आसानी होगी। देश में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होंने लगेंगे। और फिर, अभी तो भारत के पास 65,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार भी उपलब्ध है, यदि ब्याज दर कम करने से कुछ विदेशी पूंजी पलायन भारत से अन्य देशों के ओर होता भी है तो (हालांकि इसकी सम्भावना बहुत ही कम है क्योंकि भारत में विदेशी निवेश एवं विदेशी मुद्रा का आंतरिक प्रेषण भी भारी मात्रा में होता दिखाई दे रहा है) यह विदेशी मुद्रा भंडार भारत के आड़े वक्त में काम आएगा।

हमारी सरकार जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए तत्परः कश्यप

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गरीब किसान सहित सभी वर्गों के विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मंत्री श्री केदार कश्यप आज कोण्डागांव जिले के अतिसंवेदनशील मर्दापाल में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री कश्यप ने इस मौके पर 8.52 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले 54 विकास कार्यो का भूमिपूजन किया। इनमें 39 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 15 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। श्री कश्यप ने शिविर में शासन के योजनाओं के तहत हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण किया। जनसमस्या निवारण शिविर में 354 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के कारण प्रदेश की महिलाएं लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। साथ ही धान के मूल्य में वृद्धि से किसान और तेंदूपत्ता के मूल्य में वृद्धि से वनोपज संग्राहक खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शासन हर गरीब परिवार को पक्के छत उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में की गई घोषणाओं पर क्रियान्वयन करते हुए आज यहां 8 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया है। जनाकांक्षाओं को पूरा करने वाले ये विकास कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने जनसमस्याओं के समाधानकारक निदान पर जोर दिया और कहा कि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधा, खाद-बीज वितरण सहित विभिन्न सेवाओं को बेहतर ढंग से पहुंचाया जाएगा। जनसमस्या निवारण शिविर में स्वास्थ्य जांच भी की गई। यहां 106 मरीजों का उपचार एलोपेथिक पद्धति से और 36 मरीजों का उपचार आयुष पद्धति से की गई। यहां पशुधन विकास विभाग द्वारा भी 11 हितग्राहियों को पशु और कुक्कुटों के लिए औषधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत बस्तर की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, कोंडागांव जिला पंचायत के सदस्य श्री बालसिंह भारती, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री निकिता मरकाम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

कलेक्टर-एसपी ने की जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा

पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने एवं सूचना तंत्र को मजबूत करने पर जोर

रायपुर। बलौदाबाजार जिलें के कलेक्टर श्री दीपक सोनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने आज जिलें के कानून व्यवस्था को लेकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में सभी एसडीएम एवं एसडीओपी को जमीनी स्तर में सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए पुलिस की गश्ती बढ़ाने पर के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने गांवों में समय-समय पर शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कराने, धार्मिक स्थलों पर सतत रूप से निगरानी रखने के निर्देश संबधित अधिकारीयों को दिए है।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा रैली, धरना एवं प्रदर्शन करने या अनुमति प्राप्त करने से पहले आयोजन एवं व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, उसके बिना अनुमति नही दी जाएगी एवं उक्त नियमो के पालन नही करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में श्री दीपक सोनी ने कहा की गांवों में किसी प्रकार की विवाद या समस्या होने की जानकारी मिलने पर तत्काल तहसीलदार एवं थानेदार साथ ही गांव ही पहुंचकर समस्या का निराकरण करें। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में भी किसी भी प्रकार विवाद होने पर वन विभाग के द्वारा भी तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए है। सोनी ने कहा राजस्व एवं पुलिस अमला प्रशासन की रीढ़ है अतः आप सभी आपस में समन्वय के साथ बेहतर कार्य करें। इसके साथ ही जिलें में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करवाते सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास करे। इसके लिए आप सभी त्वरित रूप से जिलें में जितने भी ब्लैक स्पॉट है, उनका चिन्हांकन शीघ्र करें। इस कार्य में लोक निर्माण विभाग एवं आरटीओ भी मदद ली जाए। टीम शीघ्र ही इन स्थानों का चिन्हांकन कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत मुझे प्रस्तुत करें। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने आपसी समन्वय के साथ कार्य करने निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए है। उन्होने ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने जोर दिया। बैठक में अपर कलेक्टर सुश्री दिप्ती गौते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम, एसडीओपी, टीआई और तहसीलदार उपस्थित थे।

पंडरी बस स्टैंड की रिक्त जमीन जेम्स एवं ज्वैलरी पार्क के लिए उपयुक्त

सराफा कारोबारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र

रायपुर। सराफा कारोबारी लंबे समय से प्रयासरत्त हैं कि राजधानी रायपुर में सर्वसुविधायुक्त जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क का निर्माण हो सके इसके लिए रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के नेतृत्व में लगातार शासन स्तर पर बातचीत के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। पहले भी छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा सारी औपचारिकताएँ पूर्ण कर योजना को कार्यशील करने हेतु प्रस्ताव बन चुका था,किंतु अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया। अब राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर पूर्ण विश्वास है कि वे व्यापार हित में इसे स्वीकृति प्रदान करेंगे इसी उम्मीद में आज उनसे मिलकर मांगपत्र सौंपना था पर मुलाकात नहीं हो पाने की स्थिति में उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मिलकर उनके नाम का ज्ञापन सौंपा। मालूम हो कि पूर्व में जहां पर पंडरी में बस स्टैंड संचालित हो रहा था वह अब बस स्टैंड के भाठागांव स्थानांतरित हो जाने के बाद रिक्त है। चूंकि यह शहर के बीचो बीच व सुरक्षित क्षेत्र में हैं इसलिए इस भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जेम्स एवं ज्वैलरी पार्क का निर्माण होता है तो इससे शासन के राजस्व में वृद्धि एवं सराफा व्यवसाय के विस्तार की संभावना बढ़ेगी वर्तमान में यह भूमि लगभग 8.50 एकड़ है इस हेतु पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जेम्स एवं ज्वैलरी पार्क हेतु योजना बनायी गई थी और इस हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा सारी औपचारिकताएँ पूर्ण कर योजना को कार्यशील करने हेतु धरातल पर लाया गया था किंतु अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया अतः आप से सनम्र निवेदन है की जेम्स एवं ज्वैलरी पार्क का निर्माण पंडरी बस स्टैंड की रिक्त भूमि पर हो सके इसलिए इसे शासन की स्वर्णिम योजनाओं में सम्मिलित करने की कृपा करे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है की आप हमारी इस माँग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में श्री कमल सोनी, प्रकाश गोलछा, हर्षवर्धन जैन, पवन सोनी, गौतम लोढ़ा, संजय कानूगा, प्रकाश सोनी, विजय सोनी व अन्य सराफा कारोबारी शामिल थे

सहकारी बैंक से 52 लाख का किया गबन

रायपुर। राजधानी रायपुर में लाखों रुपये का गबन करने का मामला सामने आया है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के दो अधिकारियों ने मिलकर 52 लाख रुपये गबन कर लिया। मामले में एफआईआर होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की खोजबीन कर गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी शरद चंद्र गांगने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा प्रबंधक ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट लिखाई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि बैंक की विजिलेंस सेल की ओर से 23 अगस्त 2023 को बैंक की शाखा सीओडी में निरीक्षण के दौरान शाखा में पदस्थ कनिष्ठ लिपिक चन्द्रशेखर डग्गर के बचत अमानत खाता और शाखा के सेवानिवृत्त सहायक लेखापाल अरूण कुमार बैसवाडे के बचत अमानत खाता का परीक्षण करने पर मासिक वेतन की राशि जमा होने के बावजूद अत्यधिक आर्थिक लेन-देन किया गया था।

प्रदेश में एक्टिव हुआ मानसून, आईएमडी का बारिश को लेकर अलर्ट जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में करीब महीनेभर भीषण गर्मी की मार झेलने के बाद प्रदेश के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। रायपुर सहित कई इलाकों में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने से लोगों को राहत जरूरी मिली है, लेकिन उससे भी ज्यादा राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले पांच दिन तक गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग का कहना है कि दुर्ग, राजनांदगांव में मानसून सक्रिय होने के 24 घंटे भीतर ही रायपुर से बिलासपुर पहुंच गया। हालांकि रायपुर में मानसून चार दिन लेट पहुंचा। वहीं एक-दो दिन में मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाएगा। मानसून के एक्टिव होने के साथ ही पूरे प्रदेश में आगामी सप्ताह में बारिश और गरज-चमक के बौछारें पड़ने की संभावना है। इधर, रायपुर सहित आसपास के इलाकों में बादल और बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

हालांकि आगामी 23 से 25 जून तक बारिश की गतिविधि में थोड़ी कमी रह सकती है। इसके बाद झमाझम बारिश के आसार हैं। अभी दो दिनों तक तेज वज्रपात, गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। फिलहाल शनिवार को रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि एक पूर्व-पश्चिम द्रोणिका राजस्थान से मणिपुर तक 0.9 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बिहार और उससे लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर -पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भाजपा बताये छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कब लागू होगी

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि शराब बंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बतायें शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिये बढ़ चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाईयों दोनों के जुबान पर ताला लग गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एयर कूल्ड आहाते बनाकर शराब बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। आहाते आबंटन में बड़ा घोटाला साय सरकार ने किया है। आहातों के नाम पर सरकार शराब की काली कमाई में लगी हुई है। पूरे प्रदेश में कुछ लोगो को चिन्हांकित कर आहाते आंबटित किये गये है। प्रभावशाली भाजपा नेताओं के अनुशंसा पर आहाते आबंटित किये गये है। भाजपा सरकार के राज में शराब की कोचियागिरी शुरू हो गयी है। राजनांदगांव एवं प्रदेश के अनेकों स्थानों से खबरे आई है कि शराब दुकानों से 200 रु. प्रति पेटी अतिरिक्त देकर कोचिये गली मोहल्ले में शराब बेच रहे है और इनको पूरा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में शराब के नाम पर वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। दुकानों में कौन सी शराब बिकेगी, कौन से निर्माता के ब्रांड राज्य में बिकेगा.

सरकार सुशासन का राग अलाप रही - कांग्रेस

रायपुर। भाजपा के राज में शांत छत्तीसगढ़ अशांत हो गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अराजकता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो गये है कि राज्य में एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाये जा रहे माबलीचिंग हो रही, थाने में चाकूबाजी हो रही सरकार सुशासन का राग अलाप रही। जबसे राज्य में भाजपा की सरकार बनी है। नागरिको को भय के माहौल जीवन जीना पड़ रहा है। अपराधी बेलगाम हो गये है। साय सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी है। मासूम बच्चियों के साथ घृणित दुराचार की घटनाये बढ़ गयी। रोज समाचारों में प्रदेश भर में तीन से चार मासूम अबोध बच्चियों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटनाओं की खबरे सामने आ रही। छह माह में प्रदेश में 86 से अधिक हत्याओं की घटना हो गयी है। लूट, चाकूबाजी, चैन स्नेचिंग तो रायपुर की पहचान बन गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी से लगे आरंग में माब लीचिंग में तीन लोगो की पीट-पीटकर हत्या कर दी जाती है। सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के बजाये उनको संरक्षण देने में लगी है।

नीट में गड़बड़ी हुई है उसे रद्द क्यों नहीं किया जा रहा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है यह नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर लीतापोती करने लागू किया गया है यह कानून भविष्य में गड़बड़ियों को रोकेगा अभी वर्तमान में जो नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है गड़बड़ियां हुई है उस पर मोदी सरकार मौन क्यों हैं? 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। छत्तीसगढ़ में बालोद जिला के दो परीक्षा केंद्र और दंतेवाड़ा परीक्षा केंद्र के बच्चे भी इससे प्रभावित हुए हैं। बालोद जिला के दो परीक्षा केंद्रों में हुई गड़बड़ी में सिर्फ एक परीक्षा केंद्र एवं दंतेवाड़ा के परीक्षा केंद्र के बच्चों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। बालोद के दूसरे परीक्षा केंद्र के बच्चों को इसकी अनुमति नहीं मिली है। दंतेवाड़ा परीक्षा केंद्र बालोद परीक्षा केंद्र के बच्चों को अब परीक्षा देने के लिए दूसरे जिला भेजा जा रहा है इससे बच्चों का खर्च भार बढ़ेगा। परिजन भी परेशान होंगे। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में यह घटनाएं हुई है यह नीट की तैयारी कर रहे बच्चों के साथ अन्याय हैं मोदी सरकार इस पर कार्यवाही करने के बजाय लीपा पोती करने में जुटी है.

352 श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए एक-एक लाख रुपए सहायता राशि स्वीकृत

रायपुर। श्रमिक हितैषी प्रदेश की विष्णुदेव सरकार में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के कुल 352 श्रमिकों को एक-एक लाख रुपए सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत राशि दी जाती है। आचार संहिता के हटने के उपरांत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। मंत्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाती है। मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है.

कोल घोटाला मामलाः मुईनुद्दीन और रोशन की बढ़ी रिमाड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार 5 कलेक्शन एजेंट्स को ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो) ने आज 22 जूनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की 7 दिन यानि 28 जून तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. वहीं पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. बता दें,ईओडब्ल्यू ने 18 जून को कोल स्कैम मामले में मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया था. ईओडब्ल्यू ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है. इन पांचो आरोपियों पर सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर 25 रुपए लेवी वसूली का आरोप है. यानि ये 5 आरोपी कोयला लेवी के पैसों का कलेक्शन करते और उसे सिंडिकेट से जुड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते थे. मामले में अन्य लोगों की होगी गिरफ्तारी.

मुख्यमंत्री की विशेष पहलः

बस्तर अंचल में आस्था के केन्द्रों पर होगी हरियाली

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर बस्तर अंचल के आस्था के केन्द्रों के आसपास आने वाले दिनों में हरियाली होगी। अंचल के इन आस्था के केन्द्रों में विशेष अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण की इस मुहिम में जनजाति समुदायों को भी भागीदार बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि जनजाति समुदाय एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ सेवी-अर्जी स्थलों पर अटूट आस्था रखते हैं। देव-माता गुड़ी स्थल के आसपास वृक्षों को देवता समतुल्य मान्यता है, गुड़ी स्थल पर स्थित पेड़ पौधों को संरक्षित रखने की परंपरा है।

पौधरोपण के इस अभियान में बस्तर अंचल के 7055 देवगुड़ी-मातागुड़ी के आसपास वृक्षारोपण के अलावा 3455 वन अधिकार मान्यता पत्र स्थलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इन सभी क्षेत्रों का कुल रकबा 2607.200 हेक्टेयर है। देवगुड़ी और मातागुड़ी के अलावा प्राचीन स्मारक आदि स्थलों के आसपास भी वृक्षारोपण किया जाएगा। यहां फलदार, छायादार पौधे यथा नीम, आम, जामून, करजी, अमलताश के पौधों के साथ ही ग्रामवासियों के सुझाव अनुसार

अन्य पौधे रोपे जाएंगे। बस्तर अंचल के 7 जिलों में 5.62 लाख पौधे रोपने के लिए बस्तर कमिश्नर द्वारा रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने सातों जिलों में वृक्षारोपण कार्य के लिए जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी का दायित्व दिया है। उन्होंने कहा है कि बस्तर अंचल में वृक्षारोपण के दिन ग्राम प्रमुख, बैगा, सिरहा, पेरमा, मांझी, चालकी, गुनिया, गायता, पुजारी, पटेल, बजनिया, अटपहरिया और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने वन विभाग के सहयोग से 15 जुलाई 2024 तक पौधरोपण कार्य को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टरों को वृक्षारोपण कार्य की सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि बस्तर संभाग में स्थापित आस्था एवं जीवित परम्पराओं के केंद्र मातागुड़ी, देवगुड़ी, गोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक, सेवा-अर्जी स्थलों को संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(5) के तहत् देवी-देवताओं के नाम से ग्राम सभा को 3455 सामुदायिक वनाधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं.

महतारी वंदन योजना बना रही महिलाओं को स्वावलंबी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में लागू की गई महतारी वंदन योजना राज्य के महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रही है। योजना राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत निर्णायक साबित हो रही है। योजना की सराहना अनेक जरूरतमंद महिलाओं के अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र के कर्मचारियों ने भी मुक्त कंठ से इसकी सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से आभार व्यक्त किया है। बालोद विकास खण्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 02 झलमला की कार्यकर्ता चन्द्रिका सिन्हा ने मिलने वाली राशि को जरूरतमंद महिलाओं के लिए मुश्किल वक्त का सहारा बताया। उन्होने कहा कि समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग के अनेक महिलाएं जिन्हे अपने जरूरी तथा अनेक छोटे-बड़े आवश्यकताओं के लिए परिवार के मुखिया के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना लागू हो जाने से प्रतिमाह उनक खाते मे 1000 रू. जमा हो जाने से अब महिलाओं को अपनी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसानी से पैसा उपलब्ध हो जाता है। इस योजना की सराहना आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 02 ग्राम झलमला की सहायिका श्रीमती रेणुका साहू ने की है। इस राशि का उपयोग अपने जरूरत के कार्यो के लिए कर पा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह उनके खाते में 1000 रू. की राशि जमा होने से उसमें आत्मविश्वास जागृत होने के साथ-साथ सुरक्षा का भी बोध हो रहा है। जिससे वे प्रसन्नचित होकर हंसी-खुशी के साथ अपनी ड्यूटी कर पा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.